● वर्ष-2
● अंक-170
रायपुर, रविवार
05 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmailĐcom

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 5 मार्च रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पत्र का अगला अंक 7 मार्च मंगलवार को प्रकाशित होगा।

अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार पर हमले

सरकार केवल आर्थिक रूप से कंगाल हो है बल्कि मानसिक रूप से दिवालिया : अजय

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। स्पीकर चरणदास महंत ने प्रथम वक्ता के रूप में मोहन मरकाम का नाम पुकारा परंतु वे सदन में नहीं थे, इसके बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर को बोलने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने गोधन योजना, आत्मानंद स्कूल, झीरम घाटी जांच, बिजली बिल हाफ, जल जीवन मिशन समेत अन्य सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी का मामला जोर शोर से उठाया । वही भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने भी चर्चा के दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से शैलेश पांडे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बचाव का प्रयास।

विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार केवल आर्थिक रूप से कंगाल हो है बल्कि मानसिक रूप से दिवालिया भी है। सरकार ने अपनी हत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा के जट में राशि का प्रावधान नहीं किया । सरकार में भ्रष्टाचार पर कहा कि पर हमारी सरकार बनने पर इसकी जांच कराएंगे और 17 दिसंबर के बाद सभी को जेल भेजा जाएगा। इससे पहले शुरुवात में चंद्राकर ने

चंद्राकर ने आगे कहा कि ये गवाह है

शर्मा कंगाल सरकार ने ऐसी मछुआ नीति बनाई है, जिसमें छोटे-छोटे मछुआरों से राशि वसूल रही है। रामवनगमन पथ को लेकर उन्होंने सीधे सीएम बघेल पर हमला किया। चंद्राकर ने कहा कि सीएम संस्कृति के स्वयंभू संरक्षक बन गये हैं। ऐसी जगह श्रीराम की प्रतिमाएं लगवा रहे हैं जहां कभी श्रीराम गए ही नहीं उन्होंने चंदखुरी, चंपारण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार मनरेगा का मद परिवर्तन कर नरवा गरवा में चारागाह के नाम पर गौदान बना रही है जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है।

एक मंत्री झीरम का चश्मदीद

इसी चर्चा में शिवरतन शर्मा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि झीरम घाटी मामले में सबूत होने के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं किया क्योंकि आप के मंत्रिमंडल का एक सदस्य उसमें शामिल है। शर्मा ने कहा कि कवर्धा में आज हो क्या रहा है पहले क्या हुआ था। झंडा फेंक

अपमानित किया गया । और कार्यवाही किस पर की गई आरोपियों के बजाए पीड़ितों पर। अब भी कल भी झंडा फेंका गया। एसपी के हाथ टूट गया प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति क्या है?

बस्तर आज जल रहा है और उसका पूरा परिणाम प्रदेश को भोगना पड़ेगा। बस्तर में जो हो रहा वह पूरे प्रदेश को चपेट में लेगा। धर्मांतरण की वजह से जो स्थिति बनी है उसे धार्मिक और सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति में खराब है। शर्मा ने कहा संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे शंकराचार्य के शिष्य हैं पर यहां भीष्म पितामह बन कर आंख मूंदे बैठे है।

प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया-नेता प्रतिपक्ष

चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बेरोजगारी, पीएम आवास समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. चंदेल ने कहा कि रये सरकार झूठ की इमारत पर टिकी है. सरकार ने हर वर्ग को ठगा है. समाज का कोई वर्ग सरकार से खुश नहीं है. सरकार की नीति और नियत अलग है. उन्होंने कहा कि प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है. जनादेश मिला है तो उसका सम्मान करना चाहिए. जब से सरकार आई है लोकतंत्र की हत्या हो रही है. चंदेल ने कहा कि 22 मार्च 2022 को पंचायत मंत्री ने इसी सदन में चार अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की गई थी, लेकिन निलंबन नहीं किया गया. विधायिका का इतना बड़ा अपमान पहले कभी नहीं हुआ. प्रदेश में विधानसभा प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है. कलेक्टर विधायकों के पत्र का जवाब तक नहीं देते. लोकतंत्र में निर्वाचित व्यक्ति सबसे बड़ा होता है. सरकार को आसंदी से ये निर्देश होना चाहिए कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए. वहीं चंदेल ने राजगीत के अपमान का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजकीय गीत का अपमान हुआ. जब अधिवेशन में राजकीय गीत बजा तब कोई राष्ट्रीय नेता खड़े नहीं हुए. ये छत्तीसगढ़ का अपमान है. चंदेल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते पांच हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है. जब से ये सरकार बनी है, सारी नियुक्तियां बंद है. युवा हताश और निराश हैं. बेरोजगार युवा फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तब लोगों ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस का बहुमत है।

ब्रज की होली में डूबे रसिक

बांकेबिहारी ने भक्तों संग खेली होली

मथुरा। वृंदावन में रंगभरनी एकादशी पर दिव्य होली के दर्शन के लिए देश विदेश से भारी तादाद में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे। मंदिर प्रांगण में ठाकुर बांके बिहारी के गगन भेदी जयकारे बांके बिहारी के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा बयां कर रहे थे। अबीर-गुलाल और रंग के ऐसे गुबार उड़े कि मंदिर की आभा सतरंगी दिखने लगी। मंदिर प्रांगण रंग बिरंगे फूलों से अट गया। भीड़ को देखते हुए सेवायत गोस्वामी द्वारा सुबह तय समय 8ः45 से लगभग एक घंटे पहले ही ठाकुर जी के पट खोल दिए। अनुमान के मुताबिक दिन भर में करीब पांच लाख से अधिक भक्तों ने वृंदावन की होली का आनंद लिया। पट खुलते ही लोगों की भीड़ जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश कर गई। सेवायतों ने रजत सिंहासन पर श्वेत पोशाक धारण कर विराजमान ठाकुरजी पर स्वर्ण पिचकारी से केसर निर्मित सुगंधित रंग डालकर परंपरागत होली का शुभारंभ किया। इसके बाद अबीर-गुलाल और फूलों की होली का आनंद लिया। सेवायतों के द्वारा टेसू के फूलों, केसर मिश्रित प्राकृतिक रंगों को पिचकारियों में भरकर श्रद्धालुओं पर वर्षा की गई। रंग और गुलाल में सराबोर हो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

हर कोई ठाकुर बांके बिहारी की एक झलक पाने को आतुर था। मंदिर के चौक में भीड़ का आलम यह था कि पैर रखने तक जगह नहीं थी। वृंदावन आए श्रद्धालुओं ने ठाकुर बांकेबिहारी संग होली खेलकर खुद को धन्य महसूस किया। दिल्ली निवासी रीना ने कहा कि यहां की होली ने उन्हें काफी आकर्षिक किया है। ऐसी होली उन्होंने पहली बार देखी है। एटा निवासी अंजली अपने परिवार के साथ बांकेबिहारी की होली में शामिल हुईं।

ठाकुर श्री बांकेबिहारी अपने रजत सिंहासन पर आरुढ़ होकर श्वेत पोशाक धारण कर होली खेलने जगमोहन में विराजे। होली खेलने के लिए टेसू के रंग, चंदन के अलावा चोवा, अबीर और गुलाल का प्रयोग किया गया, जबकि ठाकुर बांके बिहारी के लिए शुद्ध केसर का रंग बनाया गया और इस केसरयुक्त रंग को सेवायतों द्वारा सबसे पहले बांकेबिहारी जी के ऊपर स्वर्ण रजत पिचकारी से डाला गया।

मुख्यमंत्री बघेल राजधानी के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल हुए। श्री बघेल ने महिला मड़ई में स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामानों की बिक्री के लिए लगाए गए स्टॉलों के अवलोकन के दौरान मिलेट कैफे में ज्वार का बना केक काटकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया।

नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी

नई दिल्ली। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक ओर बड़ी उपलब्धि! भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो छ्रक्क को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत यह सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग छ्रक्क भी, एक बोतल छ्रक्क के रूप में मिलेगी। यूरिया के बाद डीएपी देश की दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है। जानकारी के मुताबिक, लगभग 10 से 12.5 मिलियन टन सालाना इसकी खपत होती है। जबकि, डीएपी का उत्पादन केवल चार से पांच मिलियन टन ही है। देश में बाकी डीएपी आयात किया जाता है। केंद्र सरकार ने इफको के बनाए डीएपी को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया है। बता दें, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, वह कानून है जो देश में खादों की बिक्री, मूल्य, वितरण को नियंत्रित करता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल होने से इसके व्यवसायिक रिलीज का रास्ता भी साफ होने वाला है। केंद्र सरकार के इस कदम का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। बता दें, किसानों को अभी तक डीएपी बोरी में मिलती थी, जिससे इसके ढुलाई में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नैनो डीएपी बोतल में आने से इसे उतनी ही मात्रा में आसानी से लाया जा सकेगा। साथ ही इस कदम के बाद डीएपी की कीमतों में भी कमी आने की संभावना बन गई है।

प्रमुख समाचार

लोकतंत्र पर हमला हुआ मतदान को स्वांग में बदला गया-माणिक सरकार

अगरतला। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन में जबरदस्त जीत हासिल की है और सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन बहुमत से काफी पीछे रह गए। इन सबके बीच त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लेफ्ट के बड़े नेता मानिक सरकार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नजीते अप्रत्याशित हैं क्योंकि सरकार का प्रदर्शन शून्य रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र पर हमला हुआ और मतदाताओं के मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अधिकार छीन लिया गया। लेफ्ट नेता ने कहा कि मतदान को स्वांग में बदल दिया गया। संविधान ने काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि नतीजा कुछ और है। एक बात तो साफ है कि 60 फीसदी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। सरकार ने कहा कि भाजपा विरोधी वोट बंटे, कई चीजें हुईं... लोग कहने लगे हैं कि भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने में किसने मदद की।

गजेंद्र शेखावत ने गहलोत के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा

चंडीगढ़। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी वार-पलटवार का दौर जारी है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी सामने आ गया है। अपने बयान में गजेंद्र शेखावत ने कहा कि लगभग 3 साल तक ष्टरूने मेरा नाम अनेक अवसर पर एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जोड़कर चरित्र हनन करने की कोशिश की जिसका न तो मैं और न ही मेरे परिवार का कोई प्राथमिक सदस्य, डिपॉसिटर आदि है। उन्होंने जोधपुर में मुझे इस मामले में अभियुक्त करार दिया है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि उन्होंने न सिर्फ मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की बल्कि मेरी दिवंगत मां को भी अभियुक्त करार दिया। जिसके चलते मैंने धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दूसरी ओर इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी सवाल पूछा गया था।

खांसी-बुखार के लिए जिम्मेदार इन्फ्लुएंजा का सबटाइप

नई दिल्ली। लगातार खांसी या कभी-कभी बुखार की समस्या का बड़ा कारण इन्फ्लुएंजा-ए के सब-टाइप (उप-प्रकार) एच3एन2 की वजह से हो रही है। देश में यह समस्या पिछले दो-तीन महीनों से बनी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञों ने इसके लिए इन्फ्लुएंजा-ए के सब-टाइप एच3एन2 को जिम्मेदार ठहराया है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों का कहना है कि एच3एन2 पिछले दो-तीन महीनों से व्यापक रूप से लोगों की सेहत के लिए खतरा बना हुआ है। अन्य उपप्रकारों की तुलना में इसकी चपेट में आने वाले ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशभर में खांसी, सर्दी और उबकाई के बढ़ते मामलों के बीच एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के खिलाफ भी सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऐसा मौसमी बुखार पांच से सात दिनों तक रहेगा। आईएमए की एंटी-माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए स्थायी समिति ने कहा कि ज्यादातर मामलों में बुखार तीन दिनों में ठीक हो जाता है।

ऑस्ट्रेलिया में फिर निशाना बना हिंदू मंदिर, खालिस्तान समर्थकों ने की तोड़फोड़

ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। बता दें कि शनिवार को ब्रिस्बेन के मशहूर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की। मंदिर के अध्यक्ष सतिंदर शुक्ला ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह के समय श्रद्धालु मंदिर में पूजा-पाठ के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हिंदू ह्युमन राइट्स की निदेशक सारा गेट्स का कहना है कि सिख फॉर जस्टिस की तर्ज पर इस घृणा अपराध को अंजाम दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदुओं को डराने के लिए किया गया है। बता दें कि विदेशी धरती पर हिंदू आस्था पर चोट करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के कैरम डाउन इलाके में स्थित श्री शिवा विष्णु मंदिर पर भी भारत विरोधी नारे लिख दिए गए थे।

पवित्र तेल से होगा किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक, छह से आठ मई तक चलेगा समारोह

लंद। ब्रिटेन ने किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस समारोह के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल को खास तौर पर येरूशलम के एक चर्च में पवित्र किया गया है। बकिंघम पैलेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक समारोह छह मई को होना है। समारोह में उपयोग होने वाले तेल को येरुशलम के चर्च ऑफ द होली सेपल्चर में एक समारोह में पवित्र किया गया है। बता दें, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर शहर के सबसे पवित्र ईसाई स्थलों में से एक है। बकिंघम पैलेस की ओर से बताया गया कि वेस्टमिंस्टर एब्बे में एक धार्मिक समारोह के दौरान क्रिस्म तेल को किंग चार्ल्स के सिर, छाती और हाथों पर प्रतीकात्मक रूप से छुआया जाएगा। चार्ल्स के अलावा उनकी पत्नी कैमिला का भी इसी पवित्र तेल से राज्याभिषेक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, यह तेल जैतून के दो पेड़ों को काट कर निकाला गया है।

छत्तीसगढ़ में दारोमदार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर!

आदिति फडणीस

दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर केंद्र की गाज गिरने के बाद क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगली कतार में हैं? प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ), कोयला लेवी वसूली मामले के तार जोड़ने की कोशिश में है जिसके तहत खदान से उपयोगकर्ता तक कोयला पहुंचाने की व्यवस्था के लिए ई-ट्रांसपोर्टेशन परमिट की जगह मैनुअल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ने ले ली।

सूर्यकांत तिवारी नाम के व्यक्ति और कुछ अफसरशाहों द्वारा संचालित कार्टेल के इशारे पर ऐसा किया गया था और इसके लिए कथित तौर पर कई वरिष्ठ राजनेताओं को भुगतान भी किया गया था। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के राजनीतिक नेतृत्व के साथ वसूली करने वालों के संबंध जोड़ते हुए क्या ईडी अपनी जांच पूरी करेगा और चार्जशीट दाखिल कर पाएगा, यह देखा जाना बाकी है। फिलहाल कांग्रेस सरकार के सामने चुनौतियां बहुत कम हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही अधिकांश वक्त तक हाशिये पर ही रही है जब वह विधानसभा की 90 सीट में से केवल 15 सीट जीत सकी थी।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी के काम से जोड़ा गया है, हालांकि वह पिछले विधानसभा चुनावों में अपने गढ़ को ही बचाने में असमर्थ थे। कुछ महीने पहले भाजपा ने धरमलाल कौशिक की जगह तीन बार के विधायक नारायण चंदेल को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। जांजगीर-चांपा से विधायक और राज्य विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष चंदेल भी बघेल की तरह कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं।

भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस विधानसभा और स्थानीय निकाय के सभी पांच उपचुनाव जीत गई। पिछले पांच वर्षों में पार्टी ने सभी जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में भी जीत हासिल की है। सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी),

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए कोटा बढ़ाने पर आपत्ति जताने वाली राज्यपाल अनुसूया उइके के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पार्टी को अतिरिक्त बढ़त मिली। छत्तीसगढ़ में आरक्षण कोटा अब 76 प्रतिशत तक है जो देश में सबसे अधिक है। लेकिन कांग्रेस भी उस जगह पर समस्याएं पैदा करती है जहां कोई समस्या मौजूद नहीं होती। शुरुआत में 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद, राज्य में कांग्रेस के नए चेहरे को पेश करने की राहुल गांधी की योजना के तहत, ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुना गया था।

वर्ष 2018 के चुनाव के बाद बघेल और राज्य के अन्य बड़े कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव दिल्ली से यह आश्वासन पाकर लौटे थे कि उन दोनों को शीर्ष पद दिया जाएगा लेकिन जब वह रायपुर पहुंचे तो साहू के समर्थक जश्न मनाते हुए आतिशबाजी कर रहे थे। कछुए-खरगोश की कहानी की तरह साहू ने दौड़ जीत ली थी। दोनों हवाईअड्डे पर फिर लौटे और वापस दिल्ली चले गए, जहां अहमद पटेल ने मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों के आधे-आधे कार्यकाल की बात की। इसी व्यवस्था के तहत साहू को गृहमंत्री बनाया गया था। इसके बाद कोविड-19 आया जिस कारण अहमद पटेल का निधन हो गया। अब सिंह देव के पास बस आश्वासन के शब्द ही बचे थे जिसके मुताबिक उन्हें सरकार के कार्यकाल की दूसरी अवधि में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना था। जब बघेल ने अपने पद से हटने से इनकार कर दिया तब सिंह देव ने अपना विरोध तेज कर दिया।

सिंह देव अब भी नाखुश हैं, लेकिन बघेल का कद बढ़ गया है। उन्हें हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में प्रचार में शामिल किया गया था। उन्होंने रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन का आयोजन किया। उन्हें गांधी परिवार का विश्वास हासिल है। मुख्यमंत्री के रूप में बघेल यथार्थवादी और हठधर्मिता से मुक्त हैं। उनकी सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। किसानों से गोबर खरीदने की योजना ने सरकार के नरम हिंदुत्व से जुड़े कई सिद्धांतों को बढ़ावा दिया लेकिन यह एक तथ्य है कि बघेल ने भाजपा को हिंदुत्व कार्ड खेलने की अनुमति नहीं दी है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। किसानों से खरीदे गए गोबर को 3500 से अधिक सरकारी गौशालाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसे उर्वरक और अन्य उत्पादों में बदल दिया जाता है। अगला कदम इन्हें औद्योगिक पार्कों में बदलना है। अगर रमन सिंह की जीत में सार्वजनिक वितरण सेवा (पीडीएस) से जुड़े सुधारों का हाथ था तो बघेल ने भी अपनी तरफ से अनाज की खरीद का वादा किया था। छत्तीसगढ़ का कोई भी किसान विरोध नहीं कर रहा है या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग नहीं कर रहा है क्योंकि वे जानते हैं कि राज्य सरकार उसकी सारी फसल खरीद लेगी।

राज्य में सरकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को नकद सहायता देती है और इसने स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा सरकार ने स्थानीय त्योहारों के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश देने के साथ ही स्थानीय खेलों और व्यंजनों के महत्त्व पर भी जोर दिया और राज्य के गीत और राज्य के प्रतीकों को पेश करके स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री अपने 'भेंट-मुलाकात' कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं, जिसके तहत वह पहले ही 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। अगर बघेल भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे से बच निकलते हैं तब राज्य में कांग्रेस की संभावना अच्छी है। लेकिन यहां 'अगर' अहम है।

रात में हो रहा था रेत का अवैध परिवहन ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चालक की मौत

कोरबा। रेत खदानों के आवंटन के लिए नए नियम के चक्कर में जिले के रेत खदानों का आवंटन नहीं हो सका है। इस कारण अब शहरी.उपनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रेत तस्कर सक्रिय हो गए हैं जो रात के अंधेरे में नदी.नाला के किनारे से रेत खनन कर ट्रैक्टर.ट्रॉली के जरिए अवैध परिवहन कर रहे हैं। रात से लेकर सुबह तक अंधेरे में रेत का अवैध कारोबार चलता है, लेकिन न तो खनिज विभाग कार्रवाई कर रही है और न ही प्रशासनिक व पुलिस अमला, जबकि शहर के भीतर ही खुलेआम रेत का अवैध परिवहन हो रहा है।

रातभर ट्रैक्टर.ट्रॉली में सड़क पर रेत परिवहन करते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में खपाया जाता है। आउटर में कुदुरमाल के पास हसदेव नदी के किनारे से रेत खनन और परिवहन चल रहा है, जहां गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात अवैध रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टर.ट्रॉली के बेकाबू होकर पलटने से

चालक गौतम कुमार धनुहार 26 निवासी परसाभांठा की मौत हो गई। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

एनजीटी की गाइडलाइन के आधार पर मानसून लगते ही 16 जून के आसपास नदी-नाला किनारे से रेत खनन पर प्रतिबंध लग जाएगा। 4 माह बाद 16 अक्टूबर को प्रतिबंध हटेगा। इस तरह 4 माह तक रेत उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बीते वर्ष 16 अक्टूबर को प्रतिबंधित अवधि समाप्त होने के बाद शहर के गेरवाघाट रेत खदान समेत 20 खदानों में अब तक आवंटन के इंतजार में वैध खनन शुरू नहीं हो सका है साढ़े 4 माह से नए नियम में विभाग उलझा हुआ है।

दो दर्जन वैध रेत खदान है, लेकिन अवैध रेत खदान की संख्या इससे दोगुना है। अभी 20 वैध रेत खदान आवंटन के इंतजार में हैं, लेकिन दूसरी ओर उनमें से अधिकांश खदान से अवैध रेत खनन और परिवहन जोरों पर है। शहर में मोतीसागर पारा, गेरवाघाट, ढेंगुरनाला के साथ ही शहर के समीप भिलाई खुर्द, बरबसपुर, कुसमुंडा के करीब बरमपुर, छिरहुट, खोलर नाला, बालको में केसला और चुईया नाला, कटघोरा के डुड़गा, उरगा बरीडीह कुछ ऐसी खदानें हैं।

भाजयुमो मंडल नगरी ने सीएम का पुतला फूंका

नगरी। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल नगरी द्वारा भैयाथान मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह के ऊपर रेत माफिआओं द्वारा जानलेवा हमले एवं प्रदेश मे बिगड़ते कानून व्यवस्था के विरोध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया।

पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई है। आए दिन भाजपा के लोगो पर जानलेवा हमला हो रहा है। जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है।

भाजयुमो मंडल अध्यक्ष नगरी सुनील निर्मलकर ने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था के लिए भूपेश सरकार जिम्मेदार है। इस अवसर पर जिला महामंत्री प्रकाश बैस, वरिष्ठ भाजपा नेता नागेन्द्र शुक्ला, मंडल प्रभारी रवि दुबे मंडल, मंडल अध्यक्ष मोहन नाहटा, धमतरी मंडल अध्यक्ष विजय साहू, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य युवा मोर्चा निखिल साहू, मंडल महामंत्री हृदय साहू, राजेश गोसाई, कुकरेल महामंत्री संजय शांडिल्य,मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा नगरी

सुनील निर्मलकर, जिला कार्यसमिति सदस्य संत कोठारी, संजय सारथी, मनीष शर्मा, सत्यवती नेताम, चेलेश्वरी साहू, सुलोचना साहू, भुनेश्वरी धृतलहरे,महामंत्री यशवंत साहू, जन्मेजय साहू, बलजीत छाबड़ा, गुरू प्रसाद साहू, अश्वनी निषाद, भूपेन्द्र साहू, आतिश देवांगन देवीचंद ढेलडिया गज्जु शर्मा नरेन्द्र नाग दीपक डागा नीलम साहू व्यूमेश साहु करण सेन कमल पटेल अरुण प्रजापति राजा पवार विकास जैन सौरभ नाग यश साहु कमलेश साहु मोंटी यदु अजय ध्रुव रुपेश साहू नरेन्द्र साहु देवेन्द्र प्रजापति प्रशांत साहू सोमु सोनी सहित भारतीय जनता पार्टी मंडल नगरी के कार्यकर्ता गण एवं युवा मोर्चा के युवा बडी संख्या में उपस्थित थे। भाजयुमो ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नगरी को ज्ञापन सौंपा।

मशाल रैली में श्रवण मरकाम शामिल हुए

नगरी। 28 फरवरी को भाजपा जिला धमतरी के नेतृत्व में मोर आवास-मोर अधिकार की माँग को लेकर प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के जनता को आवास से वंचित रखने के विरोध में भाजपा धमतरी व हितग्राहियों के द्वारा ज़िला स्तरीय मशाल रैली निकालकर नगर घड़ी चौक से पैदल चलकर एसडीएम कार्यालय पहुँचकर ज्ञापन सौंपा गया। उक्त मशाल रैली में सिहावा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रवण मरकाम भी शामिल हुए। श्री मरकाम ने कि केन्द्र की मोदी सरकार गरीब लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बना कर दे रही हो वहीं प्रदेश की भूपेश सरकार गरीब लोगों से उनका आशियाना छिनने का काम कर रही।

युवा कांग्रेस ने रसोई गैस के बढ़े दाम पर सिलेंडर लेकर किया विरोध

जगदलपुर। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी पलक वर्मा, सह प्रभारी इक़बाल गरेवाल, प्रियंका, प्रदेश उपाध्यक्ष जिशान कुरैशी, लोकसभा प्रभारी तुकाराम चंद्रवंशी, जिला प्रभारी मनोज अवलम के मार्गदर्शन मे देश मे बढ़ती महगाई एवं रसोई गैसों पर दामों की वृद्धि को लेकर बस्तर जिला युवा कांग्रेस (ग्रामीण) ने प्रदर्शन किया। जिला महासचिव अभिषेक डेविड के नेतृत्व मे केशलूर चौक पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी का महंगाई स्वरूप प्रदर्शन भी किया।

उन्होंने कहा कि 2014 मे सत्ता मे आने से पूर्व यही भाजपा के नेता सदन से लेकर सड़क तक उतर कर महगाई का विरोध करते थे। तब रसोई गैसों की कीमत 410 रुपये पेट्रोल की कीमत 70 रुपये लीटर हुआ करती थी। तब ये नेताओं को ज्यादा लगता था, और आज रसोई 1100 रुपये के पार है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। लेकिन इन नेताओं के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

घरेलू रसोई गैस पर 50 रुपये एवं कमर्शियल गैस पर 350 रुपये की बढ़ोतरी कर आम नागरिकों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष भवर मौर्य,

उपाध्यक्ष कमल कर्मा, ब्लाक अध्यक्ष संतोष कश्यप, सोशल मीडिया समन्वयक विजय नाग, नरपति, नकुल मौर्य, संतोष कश्यप, तिरथुम सरपंच राजेंद्र, सुनील, पीटर, जगदीश, राहुल, सागर, किशन, पहुल प्रित, सलिम, राजू नाग उपस्थित रहे।

युकांइयो ने बढ़ती महँगाई के विरोध में किया पुतला दहन

कोरबा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा एवं संगठन प्रभारियों के निर्देशानुसार कांग्रेस की युवा इकाई ने घरेलू रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर एव बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की। देश भर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर एव रोजमर्रा के वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा के दिशा निर्देश पर कोरबा युवा कांग्रेस महामंत्री मधुसूदन दास की अगुवाई में बौंकी मोंगरा के बौंकी चौक पर भारत के पीएम का शवयात्रा निकाल कर बजरंग चौक में पुतला फुका एव जमकर प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओ ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की एव पुलिस के साथ पुतला के लिए जमकर झूमाझटकी की गई।

इस अवसर पर पार्षद शाहिद कुजूर, पवन गुप्ता, कांग्रेस कमेटी जिला सचिव नवल किशोर पंडित, छतबाई चौहान, संतोषी चौहान, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दीपक वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा को अच्छा दिन लाने के लिए वोट दिया था लेकिन देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़े बड़े वायदे कर मतदाताओं से वोट तो ले लिया था लेकिन अब वे अपने वायदे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में फिर से 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब जनता सरकार से पूछ रही है कि क्या यही हैं वो अच्छे दिन जिसका सपना चुनाव से पहले देश की आम जनता को दिखाया गया था।

ब्लास्टिंग से एसईसीएल की खदान में गिरा घर का छप्पर

बाल-बाल बचा परिवार, ग्रामीणों में डर का माहौल

कोरबा। कोरबा में एसईसीएल की कुसमुंडा खदान में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण खदान से लगे गांव में रहने वाले लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्लास्टिंग से अब बरपाली ग्राम में एक ग्रामीण के घर का छप्पर भरभराकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि छत गिरने से पहले पूरा परिवार घर से बाहर आ गया था नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। हैवी ब्लास्टिंग से प्रभावित ग्रामीण विस्थापन की मांग को लेकर खदान के भीतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

एसईसीएल की कुसमुंडा खदान से लगे गांव में रहने वाले ग्रामीण सुरक्षित नहीं है। कोयला उत्पादन के लिए खदान में होने वाली हैवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों के आवास प्रभावित हो रहे हैं। जिससे ग्रामीणों की जान खतरे में दिखाई दे रही है। खदान से सटे ग्राम बरपाली में ऐसी ही एक घटना सामने आई जहां देखते ही देखते हरिदास नामक ग्रामीण के मकान का छप्पर भरभराकर नीचे गिर गया।

इस घटना की आहट परिवार वालों को पहले ही हो गई थी। उन्होंने घर से बाहर निकलकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई। हरिदास की पत्नी ने बताया, कि वे अपने बच्चों को लेकर दोपहर के वक्त घर पर सो रही थीं तभी पड़ोसी ने उन्हें जगाया जिसके बाद वे कमरे से बाहर निकली, जिसके बाद घर की छत गिर गई। कहा जा रहा है, कि खदान में ब्लास्टिंग होने के कारण यह सब कुछ हुआ है।

हरिदास के पड़ोस में रहने वाले एक और ग्रामीण का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मेदनी बाइ नामक महिला ने बताया, कि उसके घर की दीवारें दरक गई हैं और घर की शीट भी टूट रही है। बरपाली की तरह कुसमुंडा खदान से लगे पाली पड़निया, जटराज गांव का भी यही हाल है जहां ग्रामीणों के घर ब्लास्टिंग के कारण प्रभावित हो रहे हैं। समय रहते अगर इनका विस्थापन नहीं किया गया तो बड़ा हादसा होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

आंगन में खेल रहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया

भेड़िए का पीछा करती रही और रास्ते में भेड़िए पर पत्थरों की बौछार भी कर दी।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र के ग्राम नैननार पटेलपारा में शुक्रवार की शाम को घर के आंगन में खेल रहे दो वर्षीय बच्चे को एक जंगली भेड़िया उठाकर ले गया। उसके पीछे-पीछे बच्चे को बचाने गई और बच्चे को अस्पताल भी लाई लेकिन वह उसे बचा न सकी।

मामले की जानकारी देते हुए मृतक ईश्वर की मां सुनकी मौर्य ने बताया कि शुक्रवार की शाम को दो साल का ईश्वर अपने बड़े भाई के साथ घर के आंगन में खेल रहा था, जबकि उसकी मां आंगन के दूसरी ओर सब्जी बना रही थी।

शाम करीब 6.00 बजे मां ने बेटे ईश्वर के रोने की आवाज सुनी और बाहर आकर देखा तो एक भेड़िया उसके बच्चे के ऊपर हमला कर रहा था। जब भेड़िए ने मां को देखा तो बच्चे को मुंह में दबाकर जंगल की ओर भागा। बच्चे को ले जाता देख मां भी भेड़िया के पीछे भागी।

वह तीन किलोमीटर तक पत्थरों से परेशान हो भेड़िए ने बच्चे को छोड़कर मां को जंगल में दौड़ाया। मां अपने आप को बचाने के लिए भागी, लेकिन कुछ देर के बाद भेड़िया भी वहां से चला गया।

मां ने किसी तरह रात में करीब दो घंटे तक बच्चे की तलाश की और किसी तरह उसे ढूंढकर अन्य लोगों की मदद से तोकापाल स्वास्थ्य केंद्र ले गई। जहां से उसे मेकाज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान ईश्वर की मौत हो गई।

इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है, जबकि घर के आसपास रहने वाले परिवार अब अपने बच्चों को रात में निकलने से भी मना कर रहे हैं। मृतक ईश्वर की मां का कहना है कि जंगल में रात ज्यादा होने के कारण ईश्वर उसे मिल नहीं रहा था, लेकिन जब मिला तो लहूलुहान हालत में था। शनिवार को बच्चे के शव का पीएम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सरपंच-सचिव दलाल बनकर काम न करें : नक्सली

जगदलपुर। विकास खंड ओरछा के साप्ताहिक बाजार में नक्सलियों ने पर्चे फेंक और पोस्टर लगाकर छोटे डोंगर के सरपंच हरिमाझी सहित दो अन्य लोगों को चेतावनी दी है। नक्सलियों के पूर्वी बस्तर डिविजन ने पर्चे लगाकर कहा है कि सरपंच-सचिव सरकार और प्रशासन का दलाल बनकर काम न करें। अपनी गलती को जनता के सामने आकर स्वीकार करें। नहीं तो मौत की सजा मिलेगी। जिला मुख्यालय से 12 किलो मीटर दूर भाकपा माओवादी ने बैनर पोस्टर चस्पा किया है। ग्राम बोरंड में सोलर वाटर टैंक में भी बैनर लगाया है। कुकड़ाझोर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। नक्सलियों ने सरपंच सचिव और टार्गेट लोगों को सादा जीवन जीने की चेतावनी दी। नक्सलियों के नेलनार एरिया कमेटी के समद् के हवाले से बैनर चस्पा किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है।

जल सत्याग्रह कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया

बेमेतरा। जिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपने 6 सूत्री मांग को लेकर जिला मुख्यालय में स्थित तालाब में

कमर से ऊपर तक पानी में खड़ा होकर अपनी मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी किए एवं शासन को शीघ्र ही अपनी मांग को पूरा करने के लिए, आग्रह किया गया है इस संबंध में आंगनबाड़ी सहायिका संघ के जिलाध्यक्ष विद्या जैन ने बताया कि जब तक के उनकी मांग को शासन मंजूर नहीं करेगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के द्वारा अपने 6 सूत्री मांग को लेकर बीते लगभग 25 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तहसील कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं जहां पर अपने मांग के समर्थन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं

खाद्य निरीक्षक और पीडीएस संचालक पर ठगी का आरोप

सक्ती। जैजैपुर के खाद्य निरीक्षक के खिलाफ महिला समूह ने कलेक्टर से शिकायत की है. खाद्य निरीक्षक पर उचित मूल्य की दुकान दिलाने के लिए 1 लाख रुपए लेने का आरोप है. महिला समूह का कहना है कि, सरकारी खर्च बताकर उन्हें धोखे में रखकर उनसे पैसे लिए गए हैं. जैजैपुर खाद्य निरीक्षक सुनेत जैसवाल और पीडीएस दुकान संचालक संतोष चंद्रा दोनों पर महिला समूह ने धोखे में रखकर पैसा लेने का आरोप लगाया है. वहीं इस मामले में खाद्य निरीक्षक का कहना है कि, महिला झूठ बोल रही हैं. मेरी उनसे बात ही नहीं हुई. महिला समूह का कहना है कि, जैजैपुर के ग्राम पिसौद की पीडीएस दुकान दिलाने के लिए उनसे 2 लाख की मांग की गई थी. जिस पर समूह की महिलाओं ने मिलकर 1 लाख जमा कर पीडीएस दुकान संचालक के माध्यम से खाद्य निरीक्षक सुनेत जैसवाल को दिया है. मगर गांव की पीडीएस दुकान अधिक पैसा देने पर दूसरे समूह को दे दी गई. वहीं इस शिकायत के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी खुद को बचाने में लगे हुए हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एनएच-43 पर धरने में बैठीं

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहीं हैं। वहीं पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने शुक्रवार को ह॥-43 के बीचो बीच बैठकर जाम लगा दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफजमकर नारेबाजी की। चक्काजाम की वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम होने से लोग परेशान होते रहे। बता दें कि, इस आंदोलन के बाद भी कार्यकर्ता अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो होगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा।

गोबर नहीं खरीदने पर ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

कांकेर। जिले के ग्राम पंचायत पुसावंड विकासखण्ड कांकेर के गौठान में नियमित रूप से पशु पालकों से गोबर की खरीदी नहीं करने के कारण जिप के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत के सचिव साधूराम मंडावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। ज्ञात हो कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पुसावंड गौठान के मैप पोर्टल का अवलोकन करने पर 16 से 31 जनवरी 2023 तक गोबर की खरीदी नहीं करना पाया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उच्च अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत सचिव साधूराम मंडावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

फेडरेशन ने रैली कर सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

■ मांगे न माने जाने पर 18 मार्च को होगा रायपुर में महारैली

नगरी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ब्लॉक शाखा नगरी द्वारा प्रांतीय आह्वान पर आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन के प्रथम चरण के तहत 3 मार्च केआंदोलन में समस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकारी तथा समस्त कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी व सदस्य दोपहर 3:00 बजे बीआरसी ऑफिस पास एकत्रित हुए तत्पश्चात ब्लॉक संयोजक डोमार सिंह ध्रुव के नेतृत्व में रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रस्थान कर तहसील कार्यालय पहुंच कर मुख्यमंत्री तथा मुख्यसचिव के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को ज्ञापन सौपा ब्लॉक संयोजक डोमार सिंह ध्रुव ने बताया की मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है फेडरेशन कई चरणों में आंदोलन कर शासन प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा चुका है लेकिन खेद का विषय है कि निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित हैं। संयोजक ध्रुव ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित समस्त लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति एवं एलबी सैवर्ग के कर्मचारियों की पूर्व सेवा की गणनाकर लाभ, पिंगवा कमेटी की रिपोर्ट शासन को सौंपने तथा केंद्र के सामान 38% महंगाई भत्ता व सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांग को जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कियागया तथा मांग पूरी नही होने पर द्वितीय चरण का आंदोलन 18 मार्च को रायपुर में महारैली किया जाएगा। इस प्रदर्शन व ज्ञापन रैली में समस्त विभाग के भृत्य, लिपिक, शिक्षक, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, कृषि अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, जनपद कर्मचारी, सचिव, पर्यवेक्षक महिला बाल विकास इंजीनियर ,सहित चतुर्थ वर्ग से लेकर के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। जिसमे छत्तीसगढ़ कर्मचारीअधिकारी फेडरेशन उपाध्यक्ष तरुण कुमार साहू विजय कुमार गेंद्रे, महासचिव किशोर कश्यप, सचिव गिरीश जायसवाल, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार बोर्झा, सहसचिव सुरेंद्रलोनहारे, संजय रेड्डी, आईटी सेल प्रभारी देव प्रकाश ताम्रकार प्रवक्ता केपी साहू, दिनेश कुमार साहू जिलाध्यक्ष वन कर्मचारी संघ, बीपी चंद्रा जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ, सुरेश ध्रुव अजजा सेवक संघ, जशपाल खनूजा अध्यक्ष समन्वयक संघ, कुलेशकुंजाम अध्यक्ष चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ आदि शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन

■ दुर्ग से रायगढ़ के बीच होगा इस ट्रेन का परिचालन

भिलाई। बिलासपुर से नागपुर के बाद चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के बाद एक और वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। इस ट्रेन का परिचालन दुर्ग से रायगढ़ के बीच होगा। नई वंदे भारत ट्रेन का प्रायमरी प्वाइंट दुर्ग स्टेशन को बनाए जाने का निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा लिया गया है, इसके लिए दुर्ग स्टेशन के वाशिंग यार्ड में अतिरिक्त पिट लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है।

हाई स्पीड ट्रेनों के परिचालन की श्रृंखला में छत्तीसगढ़ राज्य को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात

मिलने जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य जोन बिलासपुर द्वारा रेलवे बोर्ड से मिले संकेत के बाद नई वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

चर्चा है कि नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन दुर्ग से रायगढ़ के बीच होगा। इस तरह यह ट्रेन छत्तीसगढ़ में ही दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगी। वर्तमान में बिलासपुर से नागपुर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन चल रही है। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र से जोड़ रही है।

बताया जा रहा है कि नई वंदे भारत ट्रेन का प्रायमरी प्वाइंट दुर्ग स्टेशन को बनाया जाएगा। इसके लिए दुर्ग स्टेशन के वाशिंग यार्ड पर चौथी पिट लाइन का निर्माण किया जा चुका है। वंदे भारत ट्रेन की तकनीकी जरुरतों के मुताबिक नए बनाए गए पिट लाइन में ओएचई तार भी खींचा गया है। जबकि बाकी के तीन पिट लाइन में ओएचई तार नहीं लगाया गया है और यहां यात्री ट्रेनों के रैक वाशिंग के लिए डीजल लोको से लाया जाता है। वंदे भारत ट्रेन के लोको को रैक से अलग करने में तकनीकी दिक्कत को देखते हुए नए बनाए गए पिट लाइन पर ओएचई तार खींचा गया है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

त्रिपुरा में सरकार के शपथ ग्रहण में शरीक होंगे मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ मार्च को त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के गठबंधन की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। हाल ही में संपन्न त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 60 में से 32 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि इसके सहयोगी दल आईपीएफटी ने एक सीट जीती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, प्रधानमंत्री के राज्य के दौरे को लेकर मुख्य सचिव एस. के. सिन्हा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। एसपीजी की एक टीम भी शनिवार को आ रही है। प्रधानमंत्री आठ मार्च को नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नई सरकार आठ मार्च को शपथ लेगी।

मेघालय सरकार गठन में नया ट्विस्ट

शिलांग। मेघालय में सरकार गठन में नया ट्विस्ट आ गया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के लिए राज्य में सरकार बनाने की राह में मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं। दरअसल क्षेत्रीय पार्टी एचएसपीडीपी के दो विधायकों ने कोनराड संगमा के एनपीपी को अपना समर्थन दिया था लेकिन शुक्रवार देर शाम वापस ले लिया। संगमा ने शुक्रवार को 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंपा था। सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। पत्र में एनपीपी के 26, भाजपा के दो, एचएसपीडीपी के दो और दो निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर हैं। लेकिन एचएसपीडीपी के दो विधायकों द्वारा नाम वापस लेने के बाद मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। शुक्रवार शाम एचएसपीडीपी ने एक पत्र जारी किया जिसमें दावा किया गया कि उसने पार्टी विधायकों (मेथोडियस डखार और शाक्लियर वारजरी) को एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का समर्थन करने के लिए अधिकृत नहीं किया था।

कर्नाटक सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस

बेंगलुरु। कर्नाटक लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने हाल ही में बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा के बेटे के बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर छापा मारकर आठ करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। अब इस मुद्दे पर कर्नाटक की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है और शनिवार को कर्नाटक कांग्रेस बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन की। पुलिस ने कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो रहा है। हमने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन क्यों करेगी? अमित शाह भी बड़े झूठे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

कोर्ट ने आजम खान के बेटे के खिलाफ जारी किया वारंट

रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया है।अदीब के अलावा सपा विधायक नसीर खां सहित 6 के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया हुआ है। मामला किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले में समन जारी कर आज पेश होने के लिए कहा था। लेकिन अदीब कोर्ट नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि साल 2019 में किसानों की जमीन जबरन कब्जाने के मामले में अजीमनगर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में आजम खान के अलावा 12 लोग आरोपी है। रिपोर्ट के मुताबिक इनपर किसानों की जमीन को कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है। रामपुर की स्थानीय अदालत ने 1 मार्च को सपा विधायक नसीर अहमद खान, वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की बहन और बड़े बेटे तथा अन्य को शत्रु संपत्ति के अतिक्रमण के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया था।

कोलकाता के कांग्रेस नेता कौस्तव बागची गिरफ्तार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता कौस्तव बागची को कोलकाता पुलिस ने शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने एक निजी चैनल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, कोलकाता के बुर्तोल्ला थाने से पुलिस की एक टीम तड़के करीब तीन बजे बैरकपुर स्थित कांग्रेस नेता के आवास पर पहुंची। पुलिस ने कांग्रेस नेता से घंटों पूछताछ के बाद शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे कांग्रेस प्रवक्ता को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर खुद कांग्रेस नेता ने फेसबुक के जरिए जानकारी साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, कौस्तव बागची झुकेगा नहीं और बहुत जल्द जेल से रिहा होंगे... उनके पोस्ट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया है। बंगाल कांग्रेस कार्यकर्ता बागची की जल्द रिहाई की मांग की है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर भाजपा का पलटवार

राहुल विदेश में करते हैं देश की बुराई जांच के लिए क्यों नहीं दिया फोन

नईदिल्ली। हाल में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान भारत सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया था। अब इसी को लेकर भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की जासूसी हुई है तो उन्होंने अपना फोन जांच के लिए क्यों नहीं दिया? भाजपा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के समय फोन को टैप किया जाता था। राहुल ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने दावा किया कि इटली के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है।

भाजपा नेता ने कहा कि आज भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है, पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। तो वहीं दूसरी ओर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी चोरी-छिपे मंत्रियों का फोन टैप कराती थी। राहुल गांधी पेगासस को लेकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान को तोड़ने में राहुल गांधी लगे हुए हैं। पात्रा ने कहा कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, ये राहुल गांधी नहीं मानते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर वह कह रहे थे कि भारत एक समझौता है। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन हारमनी चाहता है, वहां राष्ट्रवाद है क्योंकि वहां येलो रिवर है। राहुल गांधी को भारत में गंगा नहीं दिखी।

संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश

की भूमि पर जाकर कहते हैं कि हम विपक्ष के नेता हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वह कहते हैं कि मेरे फोन में पेगासस था। लेकिन जब पेगासस मामले पर मोबाइल को जांच के लिए मांगा गया तब न तो राहुल गांधी ने अपना फोन दिया। उन्होंने दावा किया कि यूपीए-2 के अंदर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कह रहे थे कि सोनिया गांधी के कहने पर मेरे कमरे को बग कराया गया है और मैं जो बातें करता हूं वह सुन लेती हैं। यूपीए 2 में आरटीआई में बताया गया था कि 9000 फोन टेप होते थे और बाद में ये संख्या बढ़कर एक लाख हो गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके और कई अन्य विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाइवेयरथा और गुप्तचर अधिकारियों ने खुद उन्हें फोन करके बताया था कि बातचीत करते हुए वह सावधान रहें क्योंकि उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है।

2024 से पहले कपिल सिब्बल ने बनाया नया मंच गैर-भाजपाई नेताओं से भी मांगा सहयोग

नईदिल्ली। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने देश में मौजूद अन्याय से लड़ने के लिए एक नए मंच की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने इस काम के लिए गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं से सहयोग भी मांगा है। इसको लेकर उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन किया। संवाददाता सम्मेलन में कपिल सिब्बल ने कहा कि वह न्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए 'इंसाफ' मंच और 'इंसाफ का सिपाही' नामक वेबसाइट शुरू कर रहे है और इस पहल में वकील अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हालांकि उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह किसी नए राजनीतिक दल की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वह 11 मार्च को जंतर-मंतर पर इस पहल के संबंध में एक बैठक करेंगे और भारत के लिए दृष्टिकोण पेश करेंगे। सिब्बल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विपक्षी नेताओं और आम लोगों समेत सभी को खुला निमंत्रण है। उन्होंने अपनी पहल के लिए गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों और नेताओं से समर्थन देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ''यह राष्ट्रीय स्तर का एक मंच होगा, जिसमें वकील सबसे आगे होंगे। आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की शाखाएं भी हर इलाके में अपनी विचारधारा का प्रसार कर रही हैं, जो अन्याय को जन्म देती है। हम उस अन्याय से भी लड़ेंगे।''

कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 6 तक बढ़ाई, जमानत अर्जी पर 10 को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई की हिरासत में चल रहे मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 6 मार्च तक के लिए जांच एजेंसी की कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया की ओर से जमानत के लिए दायर की गई याचिका को भी टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। जमानत याचिका को लेकर कोर्ट सीबीआई को भी नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है।

सीबीआई ने मांगी थी तीन दिन रिमांड बढ़ाने की मांग

कथित आबकारी घोटाले में पांच दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर शनिवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को कोर्ट में पेश करते हुए उनकी रिमांड और तीन दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने दलील दी कि सिसोदिया अब भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

वहीं, दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच पूरी करने में सीबीआई की अक्षमता हिरासत का आधार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सहयोग नहीं करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता है और उन्हें खुद को दोषी मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सिसोदिया की ओर से ये भी कहा गया कि उनकी पत्नी की तबीयत काफी खराब है और वह असाध्य रोग से पीड़ित हैं।

सीबीआई ने कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग रखते हुए कोर्ट में कहा कि वह रोज रात में 8 बजे तक सिसोदिया से पूछताछ करती है और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। हालांकि इसे कोर्ट में अभी नहीं दिखाया जा सकता। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूछताछ में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे। जांच एजेंसी ने ये भी कहा कि एक दवा के चक्कर में पूरा एक दिन बर्बाद हो गया, जिसकी मांग सिसोदिया ने ही की थी। सीबीआई ने कहा कि उसका पूरा एक दिन सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया।

सीबीआई ने साथ ही कोर्ट को बताया कि कुछ दस्तावेज अभी भी उसे नहीं मिले हैं, जिसका पता लगाना है। गवाहों के सामने बैठाकर सिसोदिया से पूछताछ करनी है। इन दलीलों के बीच कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया का किससे आमना-सामने कराना चाहते हैं? इस पर सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में अभी ये नहीं बता सकते हैं।

गौरतलब है कि सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार, गिरफ्तार करने से पहले उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाये गये थे। अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।

'डबल इंजन' सरकार में दोगुना हुआ भ्रष्टाचार : केजरीवाल

- **कर्नाटक में बोले अरविंद केजरीवाल, हमें 'नये इंजन' की सरकार चाहिए**

बेंगलुरु। कर्नाटक में इस साल विधानसभा के चुनाव होने है। कर्नाटक में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर्नाटक होते हैं। कर्नाटक

में उन्होंने जबरदस्त तरीके से भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया और कहा कि अब हमें नए इंजन की सरकार चाहिए। अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा विधायक का बेटा कर्नाटक में आठ करोड़ रुपये नकद के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसकी जगह मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 'डबल इंजन' सरकार में भ्रष्टाचार दोगुना, हमें 'नये इंजन' की सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके (भाजपा) मंत्री के बेटे में से एक के पास आठ करोड़ रुपये पाए गए, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एंट्री से चूक ना जाए टीम इंडिया

नईदिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है। अब तक तीन मुकाबले हुए हैं। पहले दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली थी। लेकिन तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। तीसरा मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुआ था। इंदौर का होल्कर स्टेडियम की पिच को लेकर विवाद भी खूब हुआ। इन सब के बीच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। इंदौर टेस्ट जीतकर टीम इंडिया सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना सकते थी। लेकिन इस मुकाबले में हार मिलने के बाद टीम इंडिया का इंतजार और भी बढ़ गया है।

दूसरी ओर अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बात करें तो इंदौर टेस्ट मुकाबले को जीतने के बाद वह सीधे फाइनल में पहुंच गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारतीय टीम अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच सकती है? भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं अभी भी बरकरार है। इसके लिए चौथे टेस्ट मुकाबले में भारत को जबरदस्त जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही उसे श्रीलंका-न्यूजीलैंड के बीच मैच के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा। भारत में भारत को हराना काफी मुश्किल होता है। टीम इंडिया भी लगातार जीत होती रहती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंदौर में मिली जीत से उसका हौसला बुलंद हुआ है। 6 साल के भीतर भारत की धरती पर उसकी यह पहली जीत है। भारत के सबसे वरिष्ठ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में नौ मार्च से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट की अंतिम एकादश में जगह मिलने की उम्मीद है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स में हुई कटौती

नईदिल्ली। सरकार ने डीजल के निर्यात पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स घटाकर सबसे कम 0.50 रुपये प्रति लीटर और जेट फ्यूल पर शून्य कर दिया है, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क में मामूली वृद्धि कर दी गई है। एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई। 3 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क 4,350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति टन कर दी गई है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स को 2.5 रुपये से घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह,ऋस्न के विदेशी शिपमेंट पर टैक्स 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि टैक्स की नई दरें 4 मार्च से लागू हो गई।

बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इकॉनामी के लिए प्रेरक शक्ति

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा कि सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्र के विकास को अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति मानती है और इससे भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनने में मदद मिलेगी। मोदी ने बजट के बाद बुनियादी ढांचे और निवेश के विषय पर आयोजित एक वेबिनार में कहा कि इस साल का बजट देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा, 'हम बुनियादी ढांचे के विकास को अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति मानते हैं। भारत इस रास्ते पर चलकर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा।' मोदी ने कहा कि अब इस विकास की गति को तेज करने और 'टॉप गियर' में ले जाने की जरूरत है और इसमें 'प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नैनो-डीएपी को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में किया शामिल

नईदिल्ली। नैनो तरल यूरिया पेश करने वाली सहकारी संस्था इफको ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने उसके नैनो डीएपी उर्वरक को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भारत सरकार ने अब नैनो डीएपी को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत, इस उपलब्धि से किसानों को लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विट करते हुए कहा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक ओर बड़ी उपलब्धि! भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत, यह सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग डीएपी भी, एक बोतल डीएपी के रूप में मिलेगा।

अरबपतियों की लिस्ट में अडानी की बड़ी छलांग

नई दिल्ली। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी ने बड़ी छलांग लगाई है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी अब 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार तेजी के बीच अडानी की नेटवर्थ में भी इजाफा हुआ है। गौतम अडानी की नेटवर्थ अब बढ़कर 49.8 अरब डॉलर पहुंच गई है। गौतम अडानी की नेटवर्थ में एक ही दिन में रेकॉर्ड 5.08 अरब डॉलर का उछाल आया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई थी। इसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लग रहा था। लेकिन अब बीते चार दिनों से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में दोबारा तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ अडानी की नेटवर्थ में भी इजाफा हुआ है।

आज का भारत कई देशों में मंदी दूर करने की स्थिति में

प्रह्लाद सबनानी

आज कई विकसित देशों में जब मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है एवं ये देश आर्थिक समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं, ऐसे समय में भारत की एयर इंडिया कम्पनी ने अमेरिका एवं फ्रांस जैसे विकसित देशों की कम्पनियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा विमान समझौता सम्पन्न किया है। इस सौदे के बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका एवं फ्रांस के साथ ही ब्रिटेन में भी अब मंदी की आशंका कम हो सकती है क्योंकि अमेरिका एवं फ्रांस की कम्पनियां जो विमान भारत को प्रदान करेंगी उनका इंजन एवं अन्य कलपुर्जे ब्रिटेन की कम्पनियों द्वारा बनाये जाते हैं, अतः उक्त सौदे से ब्रिटेन को भी बहुत लाभ होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की आशंका के बीच भारत में हो रहे आर्थिक विकास के चलते अब यह कहा जाने लगा है कि भारत कई देशों में आने वाली आर्थिक मंदी को टालने में मददगार हो सकता है। अभी तक तो भारत को एक गरीब देश की संज्ञा दी जाती रही है एवं इन्हीं देशों द्वारा इसे सपेरों का देश भी बताया जाता रहा है। परंतु, भारत अब पूर्ण रूप से बदल चुका है तथा कई विकसित देशों की आर्थिक मदद करने की स्थिति में पहुंच चुका है।

एयर इंडिया कम्पनी का गैर-राष्ट्रीयकरण करते हुए इसके संचालन का दायित्व हाल ही में टाटा समूह को सौंप दिया गया था एवं टाटा समूह ने 27 जनवरी 2023 को ही एयर इंडिया के अधिग्रहण का एक साल पूरा किया है। अब टाटा समूह एयर इंडिया का कायाकल्प करते हुए विमानन के क्षेत्र में नए व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 8,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 640,000 करोड़ रुपए) मूल्य के 470 नए विमानों की खरीद कर रहा है। इसी संदर्भ में एअर इंडिया ने अमेरिका की बोइंग कम्पनी से 220 विमान एवं फ्रांस की एयरबस

कम्पनी से 250 विमान खरीदने की घोषणा की है। अमेरिका की बोइंग कम्पनी एवं फ्रांस की एयरबस कम्पनी के साथ एयर इंडिया का ऐतिहासिक सौदा हालांकि 470 विमानों के लिए हुआ है परंतु इसका स्वरूप और बड़ा भी हो सकता है क्योंकि एयर इंडिया के पास अगले 10 वर्षों के दौरान अतिरिक्त 370 विमान खरीदने का विकल्प भी मौजूद है, इस प्रकार यह संख्या बढ़कर 840 विमानों तक भी जा सकती है। यह विमान सौदा विश्व के इतिहास में अभी तक किए गए सबसे बड़े विमान सौदों में से एक है। इसके पूर्व अमेरिकन एयरलाइन कम्पनी ने वर्ष 2011 में 460 विमान एक साथ खरीदे थे।

अमेरिका के लिए उक्त समझौता आर्थिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि उक्त समझौते के सम्पन्न होते ही अमेरिका के राष्टपति जो बाइडन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर चर्चा करते समय इस समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि एयर इंडिया एवं बोइंग के बीच सम्पन्न हुए इस ऐतिहासिक समझौते से भारत एवं अमेरिका के आपसी रिश्ते भविष्य में और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वहीं अमेरिकी राष्टपति कार्यालय 'व्हाइट हाउस' की एक घोषणा के अनुसार, बोइंग और एअर इंडिया एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसके तहत एअर इंडिया बोइंग से 3,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर में 220 विमान खरीदेगी। इनमें 190 बी737 मैक्स 20 बी787, और 10 बी777एक्स शामिल हैं। इस समझौते के अंतर्गत 70 और विमान खरीदने का विकल्प होगा जिससे कुल लेन-देन का मूल्य 4,590 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। उक्त समझौते से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह ऐसे समय पर होने जा रहा है जब पूरा विश्व ही एक तरह से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

अमेरिका के साथ ही एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस कम्पनी से भी 250 विमान खरीदने की घोषणा की है। इनमें से 40 बड़े आकार के ए350 और 210 छोटे आकार के विमान होंगे। इन विमानों की खरीद के लिए एयर इंडिया द्वारा एयरबस कम्पनी के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्टपति एमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे। बड़े आकार के विमान का इस्तेमाल लंबी दूरी की उड़ानों के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 16 घंटे से अधिक की उड़ानों को लंबी दूरी की उड़ान कहा जाता है। आज फ्रांस, भारत के साथ हुई उसकी स्ट्रेटेजिक सहभागिता को लेकर बहुत प्रसन्न है।

रायपुर में कांग्रेस ने दिए कई संदेश

उमेश चतुर्वेदी

रायपुर में हुए महाधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने कई संदेश दिए। उसने वोटरों का भरोसा हासिल करने की कोशिश के साथ यह मेसेज दिया कि कांग्रेस अकेली पार्टी है, जो पूंजीपतियों की बजाय आम लोगों के सशक्तीकरण पर ज्यादा यकीन करती है। इस तरह से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स खुद को कहीं ज्यादा भरोसेमंद साबित करना चाहती है। लेकिन क्या वोटर उसे इतना भरोसेमंद मानेंगे कि वे बीजेपी को नकार सकें? क्या कांग्रेस ने महाधिवेशन में ऐसा कुछ किया है कि वह बीजेपी की नीतियों और नीयत के प्रति जनता में व्यापक पैमाने पर अविश्वास पैदा कर सके? बीजेपी, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी को बदलने का जो विचार दिया था, वे कहीं न कहीं इन आरोपों के जवाब थे। महाधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान के जिन 16 नियमों और 32 प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव तकरीबन मंजूर किए हैं, वे सभी के सभी राहुल गांधी के अनुकूल हैं। राहुल साल 2019 से ही कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं। उसके बाद अरसे तक उनकी मां सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष रहीं। 26 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खरगे ने अध्यक्ष पद संभाला। तब पार्टी आलाकमान ने यह संदेश दिया कि खरगे ही पार्टी के असली बॉस हैं। रायपुर अधिवेशन में सोनिया, राहुल और प्रियंका की गैर-मौजूदगी में पार्टी संचालन समिति ने कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के नामांकन का अधिकार खरगे को दिया। साथ ही, समिति के सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 कर दी। संदेश यह देने की कोशिश हुई कि इन फैसलों के पीछे कांग्रेस के पहले परिवार की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन पर्यवेक्षक मानते हैं कि जिस तरह कांग्रेस अध्यक्ष का स्वतंत्र चुनाव और उन्हें बॉस बताना दिखावा था, कांग्रेस कार्यसमिति के लिए संचालन समिति द्वारा लिया गया फैसला भी वैसा ही है। गांधी-नेहरू परिवार से बाहर का अध्यक्ष तो आ गया, लेकिन क्या कांग्रेस सचमुच प्रथम परिवार के प्रभाव से मुक्त होकर लोकतांत्रिक बन पाई? कांग्रेस संचालन समिति का खरगे को कार्यसमिति बनाने का अधिकार देना भले ही लोकतांत्रिक लगे, लेकिन कांग्रेसजनों को भी पता है कि अगली कार्यसमिति ठीक वैसे ही गांधी-नेहरू परिवार की मर्जी से बनेगी, जैसी बनती रही है। कांग्रेस के प्रथम परिवार ने इस दौरान एक गलती भी की है। महाधिवेशन ठेठ हिंदीभाषी इलाके छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन सोनिया ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया। कांग्रेस महाधिवेशन के बहाने सोनिया देश को सीधे संबोधित कर सकती थीं, लेकिन वह मौका चूक गईं। इस बीच, राहुल गांधी ने इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि मोदी के दबाव में मीडिया उनकी खबरें तक नहीं दिखाता, उनका बयान तक नहीं छापता। इस आरोप की कलई इस महाधिवेशन की हुई धुआंधार मीडिया रिपोर्टिंग ने खोल दी। जिस तरह विशेषकर टीवी पर कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हुई, साफ है कि कांग्रेस का महत्व मीडिया की नजर में कम नहीं हुआ है। महाधिवेशन में कांग्रेस ने अपने मिनी घोषणापत्र में कहा कि तीसरे मोर्चे की अवधारणा और गठन, चुनावों में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। मतलब साफ है कि समूचा विपक्ष उसकी छतरी के नीचे आ खड़ा हो। बिहार के पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने इस विचार का एक तरह से समर्थन भी कर दिया। लेकिन अभी शरद पवार, ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी कांग्रेस की चुनावी छतरी के नीचे आने को लेकर विपक्षी धड़े में अब भी उलझन है।

सिसोदिया को डर किस बात की

ललित गर्ग

किसी वकील, डॉक्टर या राजनेता को ढूंढ़ना कठिन नहीं, जो अपने विषय के विशेषज्ञ हों और ख्याति प्राप्त हों, पर ऐसे मनुष्य को खोज पाना कठिन है जो वकील, डॉक्टर या राजनेता से पहले मनुष्य हो, नैतिक हो, ईमानदार हो, विश्वस्त हो। पर राष्ट्र केवल व्यवस्था से ही नहीं जी सकता। उसका सिद्धांत पक्ष यानी नैतिकता भी सशक्त होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की ऊंचाई वहां की इमारतों की ऊंचाई से नहीं मापी जाती बल्कि वहां के नागरिकों के चरित्र से मापी जाती है। उनके काम करने के तरीके से मापी जाती है। हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी राष्ट्रीय चरित्र नहीं बन पाया। सशक्त भारत-नया भारत को निर्मित करते हुए भी राष्ट्रीय चरित्र का दिन-प्रतिदिन नैतिक ह्रस हो रहा है। हर गलत-सही तरीके से हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्त्तव्य को गौण कर दिया है। इस तरह से जन्मे हर स्तर पर भ्रष्टाचार, बेईमानी एवं चरित्रहीनता ने राष्ट्रीय जीवन में एक विकृति पैदा कर दी है। इस विकृति के दो ताजा एवं ज्वलंत उदाहरण हैं आम आदमी पार्टी के उपमुख्यमंत्री-शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में गिरफ्तारी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में चले अन्ना आन्दोलन की निष्पत्ति है। दूसरा उदाहरण है जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले गुरुग्राम के सौंदर्यीकरण के लिए रखे गये गमलों की समृद्ध लोगों द्वारा शर्मनाक चोरी का मामला।

आज प्रबुद्ध मत है कि गांधीजी ने नैतिकता दी, पर व्यवस्था नहीं। जो नैतिकता दी वह एक महान् राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष की नैतिकता थी, लेकिन नैतिक एवं चरित्रसम्पन्न राष्ट्र बनाने की नहीं। हालांकि गांधीजी ने उस नैतिकता को स्थायी जीवन मूल्य बनाया था। पर सत्ता प्राप्त होते ही वह नैतिकता खिसक गई। जो व्यवस्था आई उसने विपरीत मूल्य चला दिये। हमारी आजादी की लड़ाई सिर्फ आजादी के लिए थी- व्यवस्था के लिए नहीं थी, चरित्र एवं नैतिकता सम्पन्नता राष्ट्र बनाने के लिये नहीं। यह बात मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले से स्पष्ट सामने आती है। भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी कितनी अधिक भ्रष्टाचार में डूबी है, मनीष सिसोदिया एवं सतेन्द्र जैन की गिरफ्तारी से साफ उजागर होता है। बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आप के कार्यकर्ता एवं नेताओं द्वारा जिस तरह का आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, वे जनजीवन को अस्त-व्यस्त करने पर तुले हैं, ईमानदार हैं तो यह विरोध क्यों? दूध का दूध, और पानी का पानी हो जाने दें। मोदी सरकार पर केन्द्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि लंबी पूछताछ, जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद ही कोई एजेंसी इस प्रकार का कड़ा निर्णय ले पाती है। खासकर मामला किसी कुर्सी पर विराजित बड़े नेता का हो, बड़ी राजनीतिक हस्ती का हो। यदि सिसोदिया बेगुनाह हैं, तो उनमें न डर होना चाहिए एवं न ही बौखलाहट। क्रांति करने एवं क्रांतिकारी भ्रष्ट मूल्यों पर शराब घोटाला करने में जमीन-आसमान का अंतर है, जो जनता भलीभांति समझती है।

आज हमारी व्यवस्था चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो, चरमरा गई है। दोषग्रस्त हो गई है। उसमें दुराग्रही इतना तेज चलने लगे हैं कि गांधी रूपी नैतिक मूल्य बहुत पीछे रह जाते हैं। जो सद्प्रयास किए जा रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं। प्रगतिशील कदम उठाने वालों ने और समाज सुधारकों ने अगर व्यवस्था सुधारने में मुक्त मन से सहयोग नहीं दिया तो ....कहीं हम अपने स्वार्थी उन्माद में कोई ऐसा धागा नहीं खींच बैठें, जिससे पूरा कपड़ा ही उधड़ जाए। यह पूरा कपड़ा उघाड़ने का ही, सम्पूर्ण पीढ़ी को भ्रष्ट बनाने का जरिया। वरना तीन दिन से जेल के शिकंजों में जकड़े व्यक्ति के नाम पर दिन भर रेडियो पर सन्देश प्रसारित करते हुए परीक्षा दे रहे बच्चों को प्रेरणा देने की कुचेष्टा न होती। बात सिसोदिया या जैन तक ही सीमित नहीं है, यह भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का जहर नीचे तक पहुंच रहा है। मुख्य बात है राष्ट्रीय चरित्र केवल शिक्षा एवं प्रतीकों के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता बल्कि समाज और राष्ट्र के नेतृत्व वर्ग की कथनी और करनी एक होनी चाहिये, नीति एवं नीयत एक होनी चाहिए, तभी राष्ट्रीय जीवन में आदर्शों के मूल्य स्थापित होंगे और आदर्श सदैव ऊपर से आता है। आज के युग में सभी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो सत्य की रेखा से कभी दाएं या बाएं नहीं चलें। जो अपने कार्य की पूर्णता के लिए छलकपट, चोरी एवं बेईमानी का सहारा न लें।

वैसे तो चोरी बहुत घृणित अपराध है, लेकिन जब कोई अमीर या पैसे वाला छोटी चोरी करते देखा जाता है तो चर्चा ऐसे होती है कि मानो बिल्ली ने कुत्ते को काट लिया है। वैसे समाज में चोरी बहुत सामान्य बात है, जगह-जगह सरकार स्वयं लिखती है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। लोग तो अपने सामान की रक्षा के लिए हर पल सजग रहते हैं, लेकिन सरकार सार्वजनिक सामान के लिए कहां-कहां सतर्कता बरत सकती है? चोरों एवं बेईमानों के रहते नया भारत- सशक्त भारत कैसे बनेगा? गुरुग्राम में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सबको पता है, दुनिया से एक से बढ़कर एक बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रतिनिधि आएंगे तो अतिरिक्त सजावट स्वाभाविक है लेकिन अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति सजावटी गमलों को चुन-चुनकर उठा ले जाए तो इससे निंदनीय, विडम्बनापूर्ण एवं त्रासद और क्या हो सकता है? भला हो किसी ने इस कृत्य का वीडियो बना लिया जिसमें बहुत आराम से दो शख्स फूल वाले गमले चुनकर लाखों के वाहन में रखते दिख रहे हैं। चोरी करते हुए भी उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वे कुछ गलत कर रहे हैं।

क्या ऐसी चोरी को नजरअंदाज कर दिया जाए? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि जो जरूरतमंद है उसे भी चोरी करने का हक दिया जाए और जो सक्षम है, उसे भी सार्वजनिक वस्तुओं में से अपनी पसंद का चुन लेने दिया जाए? शायद ऐसी चोरियां बढ़ी ही इसीलिए हैं क्योंकि लंबे समय तक उन्हें नजरंदाज किया गया है। क्या छोटे-छोटे बड़े चोरों की ऐसी जमात देश में मजबूत हो गई, जो सरकारी सामान या धन को निजी मानकर चलती है? कुछ सरकारी सामान की चोरी करते हैं तो कुछ सरकार के नियमों को धत्ता बताते हुए नियमों की चोरी करते हैं। ऐसे चोरों के नाम पर मत जाइए, उनकी बुनियादी मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। अमीर गमला चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है और कानून अपना काम करेगा, पर यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी अध्ययन का विषय है कि ऐसे लोग आखिर कैसे और क्या सोचते हैं? रोटी के लिए बहुत मजबूरी में चोरी करते गरीबों के प्रति कुछ सहानुभूति हो सकती है हालांकि कानून में ऐसी किसी सहानुभूति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हमारा संविधान गरीबों को भी कोई सामान उठा ले जाने की इजाजत नहीं देता है, तो भी अमीर सार्वजनिक सामान उठा ले जाते हैं, उन्हें तो कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब देश विकसित और समृद्ध हो रहा है तो सार्वजनिक सामान की चोरी अक्षम्य अपराध माना जाना चाहिए।

अभी पिछले दिनों आगरा में भी जी-20 के आयोजन के लिए लगाए गए गमले भी चोरी हुए थे तो पुलिस का पहरा बिठाना पड़ा था। पूर्व में दिल्ली में शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री रहते बस स्टैण्ड पर स्टील के चमचमाते बैठने एवं सिर ढंकने की छतों को निर्मित किया था। लेकिन गरीब के साथ-साथ समृद्ध लोगों ने उन स्टैण्ड को भी उखाड़े डाले एवं स्टील बेच खायी। वास्तव में सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की विकृति एवं चोरी की मानसिकता सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूलों तक पसरी है। बच्चों के दोपहर के भोजन की शिक्षकों के द्वारा चोरी की अनेक घटनाएं हैं, अब उनका शिक्षा मंत्री स्कूल-भवनों एवं शराब के घोटालों में लिप्त पाया जाये तो कौन-सा बड़ा आश्चर्य है। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षा मंत्री भला बच्चों को कैसी शिक्षा एवं प्रेरणा दे सकते हैं? गुरुग्राम में गमलों की सुरक्षा के लिए 100 सुरक्षा गार्ड लगा देना ही पर्याप्त नहीं है।

नैतिकता का देश का एकमात्र अणुव्रत आन्दोलन संचालित करने वाले आचार्यश्री तुलसी कहते रहे हैं, आज के मनुष्य को पद, यश और स्वार्थ की भूख नहीं, व्याधि लग गई है, जो बहुत कुछ बटोर लेने के बाद भी शांत नहीं होती। यह स्थिति एक संयम एवं नैतिकताविहीन समाज की रचना करती है, जहां नीचे से ऊपर तक सभी कुछ अमर्यादित एवं अनैतिक होता है। पद, यश और स्वार्थ की लालसा की व्याधि से पीड़ित है राष्ट्रीय जीवन। अब समय आ गया है कि सोच को सुनियोजित ढंग से बदला जाए, नैतिकता एवं ईमानदारी को बल दिया जाये। निजी व सार्वजनिक संपत्ति, दोनों की चोरी को एक जैसा समझा जाए। सरकार यह न बताए कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, सरकार यह कहे कि आइए, मिलकर नैतिक एवं ईमानदार समाज की संरचना करें।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

मण्डलब्राह्मणोपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

कुछ काल पूर्व अज्ञान ग्रसित होकर आत्म स्वरूप को भूल गया था और जाग्रदवस्था में स्थित वासना के फलस्वरूप स्वप्न में मेरा यह मानना था कि मैं तैजस हूँ। उसी प्रकार जाग्रत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं से निवृत्ति हो जाने पर (सुषुप्तावस्था में) मैं प्राज्ञ हूँ ऐसा मानता था; किन्तु अब मैं एक ही हूँ ऐसा अनुभव होता है। स्थान भेद के कारण वे अलग-अलग अवस्थाएँ थीं; किन्तु मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ऐसा विवेक होने से %मैं शुद्ध अद्वैत ब्रह्म हूँ यह अनुभव होता है, जिसके कारण भेदभाव की समस्त वासनाएँ (आरोपित वृत्तियाँ) दूर हो जाती हैं। साधक अपने भीतर प्रकाशित तेजोमण्डल का ध्यान करने से तदाकार बनकर परब्रह्म के स्वरूप को पाकर मुक्तिपथारूढ़ होता है और परिपक्व हो जाता है। संकल्प आदि से युक्त मन बन्धन का और उससे रहित मन मोक्ष का कारण होता है। उससे सम्पन्न (जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला) साधक चक्षु आदि बाह्य प्रपञ्चों से उपरत हो जाता है। उसमें प्रपञ्चों की गन्ध तक शेष नहीं रहती। वह सम्पूर्ण जगत् को आत्म स्वरूप में देखता है और त्यक्त अहंकार होकर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिन्तन करता हुआ यह सब कुछ आत्मा ही है, ऐसी भावना करता हुआ कृतकृत्य हो जाता है। सब प्रकार से परिपूर्ण होकर वह तुरीयातीत योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यह ब्रह्म है, लोग इस प्रकार उसकी स्तुति करते है। वह समस्त लोकों की स्तुति का पात्र बनता है, समस्त लोकों में संचार करने वाला होता है और परमात्मा रूप गगन में बिन्दु स्थापित करके (चिदाकाश में मन को विलीन करके) शुद्ध, अद्वैत, जड़तारहित, सहज और अमनस्क स्थिति रूपी योगनिद्रा में अखण्डानन्द का अनुसरण करके जीवन्मुक्त हो जाता है। उस आनन्द के समुद्र में मग्न रहने वाले (सिद्ध) योगी कहे जाते हैं। उन योगियों की अपेक्षा इन्द्रादि देवगण भी स्वल्प आनन्द प्राप्त करने वाले होते हैं। इस प्रकार परमानन्द प्रात करने वाला परम योगी होता है, यह अद्भुत रहस्य है। महामुनि याज्ञवल्क्य ने सूर्य मण्डल स्थित पुरुष से कहा हे स्वामी! आपने अमनस्क स्थिति के लक्षणों के विषय में मुझे उपदेश दिया, अब वह मुझे विस्मृत हो गया है, अत: कृपा करके पुन: उसके लक्षणों को मुझे बताएँ। वह मण्डल पुरुष बोला- बहुत अच्छा, यह अमनस्क स्थिति अतिरहस्यमय है। इसके ज्ञान से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह नित्य ही शाम्भवी मुद्रा से समन्वित होता है।

परमात्म दृष्टि से उसका अनुभव कराने वाले लक्ष्यों को देखकर सबके ईश्वर, अप्रमेय, अज, शिव (कल्याणकारी), परम आकाश, निरालम्ब, अद्वितीय, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि के एकमात्र लक्ष्यरूप सभी के कारण परम ब्रह्म को आत्मरूप में देखने वाला पुरुष हृदयगुहा में ही विहार करता हुआ निश्चय पूर्वक जानकर, भाव - अभाव आदि द्वन्द्वों से अतीत होकर, मन की उन्मनी अवस्था का अनुभव करता है।

क्रमश:...

गांधी-इरविन समझौता

इतिहास में पांच मार्च का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण दिन से जुड़ा है। 1931 में आज ही के दिन महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञान आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। इस समझौते को गांधी-इरविन समझौता कहा जाता है।

पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि गांधीजी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए वायसरॉय पर दबाव बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं।

इस समझौते की पृष्ठभूमि 1930 की है। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के नमक बनाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च निकाला, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर पहला कदम था। गांधीजी ने समुद्र तट पर पहुंचकर खुद यह नमक कानून तोड़ा था। इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। नमक आंदोलन ने पूरी दुनियाभर में सुर्खियां हासिल कीं और इस कारण लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ गई थीं। तब उन्होंने पांच दौर की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता किया, जिसे गांधी-इरविन पैक्ट कहा जाता है।

इसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। उस समय पूरा देश 23 साल के भगत सिंह की चर्चा कर रहा था, जिन्हें अक्टूबर 1930 में फांसी की सजा सुनाई गी थी। गांधीजी पर कांग्रेस के साथ-साथ देश का भी दबाव था कि वे भगत सिंह की फांसी को रुकवाएं, पर गांधी-इरविन समझौते में इसका जिक्र तक नहीं था। गांधी ने अपने पत्र में इतना ही लिखा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाए तो अच्छा है। दरअसल, वे भगत सिंह के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते थे। इसी वजह से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके दो साथियों को फांसी दे दी गई। वहीं, सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस में रहते हुए भी 20 मार्च 1931 को फांसी के विरोध में दिल्ली में एक बड़ी जनसभा की थी।

गांधी-इरविन समझौते में राजनीतिक बंदियों की रिहाई के साथ-साथ भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिला। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने की आजादी भी मिली। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को बहाल किया गया। जब्त संपत्ति भी वापस की गई। कहीं न कहीं, इस समझौते ने गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और कांग्रेस के भाग लेने का रास्ता खोला।

तीन राज्यों के चुनाव के नतीजों ने दिए चार स्पष्ट संदेश

अवधेश कुमार

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में चौंकाने वाला कोई तत्व नहीं है। वास्तव में परिणाम लगभग उम्मीदों के अनुरूप ही है। तीनों राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के चुनाव परिणामों को एक साथ मिलाकर देखें तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक, भाजपा की सीटें किसी राज्य में थोड़ी कम या ज्यादा हो, मत प्रतिशत में थोड़े-बहुत अंतर आ जाएं लेकिन अब वह पूर्वोत्तर की प्रमुख स्थापित पार्टी हो गई है।

दूसरे, एक समय पूर्वोत्तर पर एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की क्षरण प्रक्रिया लगातार जारी है। तीसरे, पूर्वोत्तर में तृणमूल के एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीद भी धराशाई हुई है। चौथे, माकपा के नेतृत्व वाले वाम दलों की पुनर्वापसी की संभावना पहले से ज्यादा कमजोर हुई है। जरा सोचिए, अगर त्रिपुरा में वामदल और कांग्रेस मिलकर भी भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सफल नहीं हुए तो इसके मायने क्या हैं?

पिछले चुनाव में यद्यपि माकपा नेतृत्व वाला वाममोर्चा सत्ता से बाहर हुआ था लेकिन भाजपा और वाम मोर्चे के मतों में ज्यादा अंतर नहीं था। इस कारण भाजपा विरोधी और वाममोर्चा के समर्थक यह मान रहे थे कि भले जनता ने सत्ता विरोधी रुझान में माकपा को बाहर कर दिया लेकिन अगले चुनाव में इसकी वापसी हो सकती है। चुनाव परिणामों ने बता दिया कि वाम मोर्चे का उदय अब दूर की कौड़ी है। निश्चित रूप से इस परिणाम के क्षेत्र के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी विश्लेषण होगा।

आखिर 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा विरोधी पार्टियां कई प्रकार के समीकरण बनाने की कवायदें कर रही हैं तो इस चुनाव का असर उस पर न पड़े ऐसा संभव नहीं। तो कैसे देखा जाए इन चुनाव परिणामों को?

यद्यपि तीनों राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण थे, पर देश का सबसे ज्यादा ध्यान त्रिपुरा की ओर था। यह पहला राज्य था जहां भाजपा ने अपने विपरीत विचारधारा वाले वाममोर्चा को पहली बार पराजित किया था। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देव के शासनकाल में स्वयं पार्टी के अंदर असंतोष के स्वर तथा सरकार की कुछ नीतियों के विरुद्ध जनता में भी विरोध देखा गया।

भाजपा ने मई 2022 में उनकी जगह माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया। कहा जा सकता है कि चेहरा बदलने से दोनों स्तरों का असंतोष थोड़ा कम हुआ। भाजपा की सीटें और मत दोनों पिछले चुनाव से घटे हैं लेकिन वह अपनी बदौलत 60 सदस्य विधानसभा में बहुमत पा चुकी है।

नगालैंड की ओर देखें तो वहां भी भाजपा का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ गठबंधन में वह छोटा साझेदार थी। उसे 20 सीटें ही लड़ने के लिए मिलीं किंतु केंद्रीय नेतृत्व ने इसके कारण पार्टी की स्थानीय इकाई में विरोध और असंतोष उभरने नहीं दिया। छोटा साझेदार होकर भी उसने एनडीपीएस के साथ मिलकर उसी तन्मयता से चुनाव लड़ा जैसे वह अन्य राज्यों में लड़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे सभी नेता वहां चुनाव प्रचार करने गए और पूरा जोर लगाया। पिछले नगालैंड की विधानसभा में कोई विपक्ष रह ही नहीं गया था। नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक सरकार के साथ चले गए थे। आगे क्या होगा अभी कहना कठिन है लेकिन भाजपा ने वहां सभी दलों के नेताओं से अपना संपर्क संबंध बनाए रखा है।

निस्संदेह, मेघालय का चुनाव परिणाम भाजपा की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। उसे स्वयं बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। पिछली बार उसे 2 सीटें आई थीं और एनपीईपी, पीडीएफ और एचएसबीसी के साथ मिलकर उसने मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस बनाया था। एनपीईपी के साथ उसका चुनावी गठबंधन नहीं था। चुनाव के बाद असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हेमंत विश्व सरमा की कोनराड संगमा से मुलाकात बताती है कि साथ मिलकर काम करने की बातचीत परिणाम के पहले ही शुरू हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस भी यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और कांग्रेस को लेकर तो बहुत उम्मीद ही नहीं थी।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्वोत्तर पर विशेष फोकस किया है। वहां अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और संवाद से अलगाववाद, क्षेत्रीय -जातीय विशेषता के भाव को भारतीय राष्ट्र भाव के साथ जोड़ने की लगातार कोशिश की। यातायात और संचार के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में सच कहा जाए तो क्रांति हुई है। सड़कें और रेलमार्ग ही नहीं हवाई यात्राओं की दृष्टि से भी आधारभूत संरचनाएं सशक्त हुई हैं।

सबसे बड़ी बात कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफस्पा को हटाने की बात अनेक पार्टियां और मानवाधिकार संगठन करते थे। उसे सही मायनों में भाजपा ने ही स्वीकार किया। आज असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि सभी राज्यों में ज्यादातर क्षेत्रों से अफस्पा हटाया जा चुका है। नगालैंड की सभा में प्रधानमंत्री ने इसे हटाने का वायदा किया। इस तरह वहां के लोगों ने लंबे समय बाद शांति, स्थिरता और आवागमन से लेकर सभी प्रकार की गतिविधियों में भयमुक्त स्वतंत्र वातावरण महसूस किया है।

इन सबके साथ पूर्वोत्तर के अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृतियों, स्थानीय परंपराओं, सोच और व्यवहार से लेकर स्थानीय विशेषताओं को भी प्रोत्साहित किया गया। इन सबका व्यापक असर हुआ है और आज पूर्वोत्तर सोच और व्यवहार की दृष्टि से समग्र रूप से भारत का बदला हुआ क्षेत्र है। इन सबकी प्रतिध्वनि चुनावों में दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी इन सारी दिशाओं में काफी कुछ किया जाना शेष है।

गांधी आज

सौ फीसदी स्वदेशी (भाग-02)

गतांक से आगे...

देहात के सैकड़ों उद्योग जो प्रोत्साहन के अभाव में मर गए या मृतवत् जीवित हैं उनका संजीवन करने की। इस बारे में शहरातियों और पढ़े-लिखों ने देहात के प्रति अक्षम्य लापरवाही दिखाई है। साल पहले देहात के लोग अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल की तो खुद बना लेते ही थे छोटे कस्बों के रहनेवाले भी अपने रोज के बहुत-सी चीजों के लिए उनके ही मुहताज थे। इसके बदले अब शहरों का विदेशों से मँगाते हैं. और जो पंधे देहातवालों के बाप दादा दस्त से करते आते थे वे बंद हो गए हैं। पर शहरातियों और प लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अत: आज का देहाती कंगाली, परावलंबन और अहदीपन का शिकार हो गया है। उसमें पचास साल पहले के देहाती की आधी भी बुद्धि जानकारी नहीं रही। देहाती कारीगर भी देहात के और सब लोगों की तरह अबुद्धि और अनाड़ी बन गया है। ग्रामवासी जिस क्षण अपनी फुर्सत का अधिकांश समय कोई उपयोगी काम करने में लगाने का निश्चय करेंगे और नगरवासी देहात की बनी चीजें काम में लाने का संकल्प करेंगे उसी क्षण देहाती और शहराती का जो संबंध आज टूट गया है वह फिर जुड़ जाएगा। इस काम में देशभक्तों की एक बड़ी सेना खप सकती है। जितने स्वदेशी-संघ आज काम कर रहे हैं उन सबके और दूसरों के लिए भी लंबा-चौड़ा मैदान खाली पड़ा है। इसके लिए अगणित उद्योगों के विषय में पक्की जानकारी प्राप्त करना, बहुतों के बारे में खोज करना और अनेक प्रकार के कारीगरों की भलाई में दिलचस्पी लेना जरूरी है। इससे उन बहुसंख्यक लोगों को ईमानदारी और इज्जत का काम करके गुजर करने का ज़रिया मिल जाएगा जो आज बिना धंधे के भूखों मर रहे हैं। 12. यह सच्ची सफल और सौ फीसदी स्वदेशी है।

संक्षिप्त समाचार

10 के दम में 26 को महिला तीरंदाजी में दिखाएंगी दम

रायपुर। खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 26 मार्च को राजधानी रायपुर में होने जा रहा है जिसका थीम रखा गया है कि 10 का दम। जिसमें महिला सब जूनियर तीरंदाज प्रतिभागी होंगी। प्रतियोगिता के प्रारंभ से पहले आज छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश मुरारका ने सर्टिफिकेट और बैनर का विमोचन किया। कैलाश मुरारका ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया के सहयोग से पूरे देश भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 खेलो को 10 प्रदेशों में अलग-अलग नाम से कराया जा रहा है और इसका नाम 10 का दम रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला आर्चरी 10 का दम प्रतियोगिता 26 मार्च को राजधानी रायपुर में कराया जाएगा जिसकी तैयारी में छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन अभी से लग गया है। आज सर्टिफिकेट, बेनर का विमोचन किया गया। मुरारका ने बताया कि 10 का दम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरे प्रदेश से महिला सब जूनियर तीरंदाज के आने की संभावना को देखते हुए छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन अभी से तैयारी में जुट गया है। मुरारका ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर 10 के दम प्रतियोगिता में पहले तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बाड़ लगाना, हॉकी, जूडो, खो-खो, तैराकी, भारोत्तोलन, वुशु तथा योग में भाग ले चुके महिला प्रतिभागियों को 10 मार्च को सम्मानित किया जाएगा।

पीडीएस के तहत माह मार्च के लिए 7,416 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय किए जाने निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली से वर्ष 2023 के चतुर्थ तिमाही के लिए प्राप्त केरोसिन आबंटन में से 7416 किलोलीटर केरोसीन का छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड एवं हाकर्स के लिए माह मार्च 2023 के लिए उचित मूल्य दुकानवार आनलाईन आबंट जारी कर दिया गया है। इसमें पीडीएस के लिए 7367 और हाकर्स के लिए 49 किलोलीटर केरोसिन सामिल है। इस आशय का पत्र खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और ऑयल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयकों को भेज दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पीडीएस के तहत प्रचलित सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डो को पात्रता होगी। नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों के लिए अधिकतम 2 लीटर केरोसीन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों को अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों को अधिकतम 2 लीटर की पात्रता होगी। वहीं हॉकर्स को 85 लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है। हॉकर्स को निर्धारित उचित मूल्य दुकान के समक्ष खड़े होकर हॉकर्स से राशन कार्डधारियों को केरोसिन वितरित कराने को कहा गया है। माह मार्च के लिए जिलेवार केरोसीन आबंटन इस प्रकार है। बस्तर जिले के लिए 336 किलोलीटर केरोसीन का आबंटन जारी किया गया है।

केशकाल घाट में रोजाना जाम

केशकाल। केशकाल घाट को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसका मुख्य कारण राजधानी रायपुर से बस्तर तक पंहुचने के लिए केशकाल घाट से ही होकर गुजरने का एक मात्र मार्ग है, केशकाल घाट को 12 मोड़ों की इस सर्पीली घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। खूबसूरत टाटामारी पर्यटन केंद्र व 9 से अधिक जलप्रपात से घिरे केशकाल घाट पर अब जाम लगना आम बात हो गई है। आपको बता दें कि केशकाल बाईपास को लेकर युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ किया गया, लेकिन विगत 8 वर्षों से बाईपास का काम अधूरा पड़ा है। भारी वाहनों के लगातार आवागमन के साथ ही घाट के मोड़ पर वाहनों के पलटने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है, जिसके चलते मुसाफिरों को घंटों घाट पर रुकना पड़ रहा है। इसका खामियाजा उन यात्रियों को भुगतना पड़ता है, जिन्हे राजधानी रायपुर से आगे की यात्रा में ट्रेन एवं हवाई यात्रा के लिए फ्लाइट पकडऩा होता है। इससे भी अधिक उन युवाओं को इसका खामियाजा उठााना पड़ रहा है, जिन्हे राजधानी रायपुर में परिक्षा देने के लिए जाने के दौरान आवागमन बाधित होने से युवाओं को अब एक दिन पहले निकलना पड़ रहा है, जिससे युवाओं को अधिक खर्च करना पड़ रहा है।

दिव्यांग के लिए आगे आया चरामेति फाउंडेशन

रायपुर। रायपुर जिले के अंतर्गत ग्राम बकतरा निवासी पिंटूराम साहू जिनकी दिव्यांगता करीब 90 प्रतिशत है के ट्रायसायकल की दोनों बैटरी खराब हो गई थी। वे जंगल सफारी के पास बच्चों के खिलौने आदि बेचने का व्यवसाय भी करना चाहते हैं। ट्रायसायकल के न चल पाने के कारण उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाई रहा था। चरामेति फाउंडेशन के राजेन्द्र ओझा ने बताया कि श्री डी के पात्रिकर, श्री हरीश भाई कोटक, श्रीमती सुभाषिनी जतिन्दर भनोट आदि के सहयोग से करीब दस हजार रूपये की दो बैटरी पिंटूराम साहू के भाई लोकेश को दी गई। खिलौने आदि के लिए भी सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने की पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा

00 संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी स्थित विप्र भवन में विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंध समिति द्वारा आयोजित संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सम्मान में संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदाय करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। यह पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह से प्रतिवर्ष प्रदाय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर साहित्य तथा कविता लेखन के क्षेत्र में विशिष्ठ योगदान के लिए छत्तीसगढ़ के कवि तथा साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। इनमें पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे को विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान-2023 से नवाजा गया। इसी तरह श्री अरूण कुमार निगम को तथा श्री काशीपुरी कुन्दन को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया। प्रत्येक को पुरस्कार स्वरूप 21-21 हजार रूपए की राशि और शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने इस मौके पर विप्र योग पत्रिका तथा विप्र महाविद्यालय के मासिक बुलेटिन का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि संत कवि पवन दीवान का छत्तीसगढ़ की माटी से गहरा लगाव था। इनके लेखन में समाज के तत्कालीन दशा का बहुत ही सुन्दर और सहज चित्रण मिलता है, जो हर वर्ग और हर समाज के लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती थी। यह वजह है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री दीवान जन-जन में काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने कहा कि संत कवि श्री दीवान को याद करना हमारे पुरखों द्वारा देखे गए छत्तीसगढ़ के स्वप्न को याद करने के जैसा है। उनकी कविता में बार-बार छत्तीसगढ़ के माटी का उल्लेख हुआ है। वे कवि हृदय बहुत भावुक, बहुत अच्छे कथावाचक और पूर्णतः निस्वार्थ व निश्छल मन के व्यक्ति थे। उन्होंने समाज के मौजूदा स्थितियों को बड़ी ही सहजता से अपनी रचनाओं में पिरोया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वे हमारे पुरखों के छत्तीसगढ़ के लिए देखे गए सपना को पूरा कर रही है। आज विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का डंका देश और दुनिया में बज रहा है। यहां लागू की गई योजनाओं को अन्य राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है। उन्होंने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में गरीब, मजदूर और व्यापारी तथा किसानों सहित सभी वर्ग के लोगों की स्थिति में काफी सुधार आया है। यहां धान बेचने वाले किसानों की संख्या और धान का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है।

पुलिस के विशेष अभियान में फरार 56 स्थायी वारंटी पकड़ाए

जगदलपुर। जिला में बेसिक पुलिसिंग अन्तर्गत शांति व्यवस्था हेतु लगातार कार्यवाही कर अपराध नियंत्रण की कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कडी में आगामी 8 मार्च को होली त्यौहार के मद्देनजर बस्तर जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में कई वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटीयों पर विशेष अभियान चलाया गया है। जिस तारतम्य में उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, एसडीओपी केशलुर एश्वर्य चंद्राकर के पर्यवेक्षण में अलग-अलग टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। बस्तर जिला के ऐसे अपराधी जो अपराध कारित कर, लम्बे समय से फरार चल रहे थे, जिस पर न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। ऐसे फरार स्थायी वारंटियो पर विशेष अभियान के तहत धरपकड़ कार्यवाही किया गया है। जिसके अन्तर्गत बस्तर जिला के थाना कोतवाली-12, थाना बोधघाट-14, थाना भानपुरी-2, थाना परपा-5, थाना नगरनार-8, थाना बस्तर-1 एवं थाना लोहण्डीगुडा-3, बकावंड-5, दरभा-5, कोडेनार-1 कुल 56 वारंटीयों को पता तलाश कर वारंट तामिल कर, संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की।

कांग्रेस नेताओं की मांग पर पैदल पार मार्ग सड़क का रेलवे ने किया निर्माण-राजेंद्र ताम्रकार

भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र ताम्रकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्लेटफार्म एक नंबर से अन्य दूसरे प्लेटफार्म में व्हीलचेयर से आने जाने के लिए पैदल पा मार्ग सड़क का निर्माण किया गया था जिसे रेल पटरी के संधारण करते समय लगभग 1 वर्ष पूर्व तोड़ दिया गया था जिसके कारण दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था इस संदर्भ में कांग्रेस के नेताओं ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर पुनर्निर्माण की मांग की गई और इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को भी ज्ञापन भेजकर हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया था और इन्होंने ज्ञापन को तत्काल संज्ञान में लेते हुए डी .आर .एम .दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर को पत्र लिख कर शीघ्र ही उक्त समस्याओं को दूर करने का अनुरोध किया था फल स्वरूप दिनांक 26 फरवरी 2023 को रेलवे के द्वारा पैदल पार मार्ग सड़क का निर्माण कराया गया तब जाकर दिव्यांगो एवं वरिष्ठ नागरिकों के व्हीलचेयर को एक प्लेटफार्म से अन्य दोनों प्लेटफार्म तक आना-जाना प्रारंभ हो सका है , जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र ताम्रकार एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि अमीर चंद अरोरा तथा दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला प्रतिनिधि लल्लन तिवारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नागेंद्र तिवारी एवं राजकुमार चौधरी और युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिवराज ताम्रकार आदि ने माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय गृह मंत्री जी तथा रेलवे के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इसी तरह भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के कई ज्वलंत समस्याओं को भी शीघ्र ही दूर करने का अनुरोध किया है ताकी यात्रियों को हो रही परेशानियों से राहत मिल सके।

बलासपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मचा हड़कंप

बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में बिलासपुर के सभी थाना अंतर्गत अवैध नशा के कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफकार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में आबकारी एक्ट अंतर्गत कुल 635 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें से 124 आरोपी (72 आबकारी व 52 एनडीपीएस प्रकरणों में) जेल भेजे गए. जिनसे 1053 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया है. आबकारी एक्ट 34(2) के अंतर्गत 72 प्रकरण में 72 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वाले 338 लोगों के खिलाफ 36(च) आबकारी एक्ट की कार्रवाई और 207 लोगों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर 185 एमवी एक्ट की कार्रवाई में वाहनों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया है।

मनरेगा से बंजर भूमि को मिला नया जीवन

- डबरी में मछली पालन कर कमा रहीं मुनाफा
- आर्थिक मजबूती से बढ़ा आत्मविश्वास

बिलासपुर। कोटा ब्लॉक के छोटे से गांव बारीडीह की श्रीमती बारात बाई गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। आर्थिक रूप से मजबूत होकर परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। उनकी सफलता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की महती भूमिका है। इस योजना से उनके खेत में डबरी निर्माण का कार्य हुआ है। डबरी में मछली पालन से उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जिससे परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी हो जा रही है। श्रीमती बारात बाई ने बताया कि एक बंजर भूमि के लिए पानी अमृत के समान होता है। गांवों के अधिकांश ग्रामीण सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते है। राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत किसानों के भूमि पर डबरी निर्माण करके जल संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर जन-जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भूमि के नाम पर बंजर जमीन थी, जिस पर खेती करना, रेत से पानी निकालने के समान था। खेती के लिए केवल भूमि ही जरूरी नहीं होता। इसके साथ फसल उत्पादन के लिए भूमि उपजाऊ भी होनी आवश्यक है।

खाली पड़ी बंजर जमीन का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं था। बंजर भूमि के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार का विकल्प भी नहीं था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत उनकी बंजर भूमि पर डबरी निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ। डबरी बन जाने से उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने इस मौके को अपनी सफलता की दिशा की ओर मोड़ते हुए डबरी में मछली पालन का कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि डबरी निर्माण से उन्हें आय का स्त्रोत तो मिला हीं साथ ही उनकी शेष बंजर भूमि भी डबरी निर्माण से उपजाऊ हो रही है। जिस पर उन्होंने फसल भी लगाना प्रारंभ कर दिया है। अब उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। श्रीमती बारात बाई ने अपनी सफलता का श्रेय शासन की मनरेगा योजना को देते हुए बताया कि योजना से उनकी बंजर भूमि को अब नया जीवन मिल गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण: विकास के दावे खोखले बेरोजगारी, असमानता और कर्जदारी बढ़ी

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कहा है कि कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, उन आंकड़ों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि विकास के दावे खोखले है और वास्तविकता यह है कि प्रदेश में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और कर्जदारी बढ़ी है, जो प्रदेश की आम जनता की सेहत के लिए खतरनाक संकेत है।

आज यहां जारी बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार प्रदेश की 73त्न आबादी गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसी हालत में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने का स्पष्ट अर्थ है कि आय की असमानता बढ़ी है और गरीब तो आय में औसतन 11त्न की वृद्धि से वंचित ही है। हकीकत यही है कि योजनकर्मियों सहित असंगठित क्षेत्र के मजदूर न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित है, जो आर्थिक असमानता में वृद्धि का बड़ा कारण है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 19 लाख को छू रही है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी सहित गैर-पंजीकृत बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी है। दूसरी ओर, सरकारी विभागों में हजारों की संख्या में पद रिक्त है। सरकारी कर्मचारियों की काम की स्थितियां भी दयनीय है और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के चुनावी वादे से यह सरकार मुकर रही है। मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार देने का एक बड़ा हथियार बन सकता था, लेकिन स्थिति यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सितम्बर तक प्रति परिवार औसतन केवल 24 दिनों का ही काम दिया है और 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या आधा प्रतिशत भी नहीं है। इसमें भी हजारों परिवारों का मजदूरी भुगतान अभी तक बकाया है। यह सरकार के रोजगार विरोधी रवैये को ही दर्शाता है।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि प्रदेश पर इस समय 90000 करोड़ रुपयों का कर्ज है और सिर्फ ब्याज भुगतान में ही हर माह लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यह कर्जदारी कुल बजट का 90त्न और स्थिर दरों पर प्रदेश की जीडीपी का 31त्न से अधिक है। यह कर्जदारी प्रदेश के विकास के लिए खतरनाक है।

किसान सभा नेताओं ने आशा व्यक्त की है कि आगामी बजट इन चुनौतियों का मुकाबला करने वाला और आम जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाकर घरेलू बाजार का विस्तार करने वाला बजट होगा।

दिव्यांग बच्चों के लिए मन में दया नहीं करुणा होनी चाहिए - चतुर्वेदी

- अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं - प्रमोद दुबे
- विश्व श्रवण दिवस पर 15 बच्चों को डिजिटल श्रवण यंत्र वितरित
- समाजसेवी अरुण सिंघानिया ने किया अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल की वेबसाइट को लॉच

रायपुर। दिव्यांग बच्चों के लिए मन में दया नहीं करुणा होनी चाहिए। जहां करुणा होती है वहीं प्रेम होता है। प्रेम से ही सभी कार्य सफल होते हैं। सिविल लाइन स्थित वृंदावन हाल में विश्व श्रवण दिवस पर आयोजित डिजिटल श्रवण यंत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी ने उक्त बातें कही। विश्व श्रवण दिवस पर अर्पण कल्याण समिति, हियरिंग केयर सेंटर एवं रोटरी क्लब ऑफ रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल के 15 बच्चों को डिजिटल श्रवण यंत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाजसेवी व प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अरुण सिंघानिया ने अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल की वेबसाइट को लॉच किया। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति गीत पर दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य से लोग भाव-विभोर हो गए और तालियों की गडग़ड़ाहट से हाल गूंज उठा। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि मूक-बधिर बच्चों को ईश्वर ने अद्भुत शक्ति प्रदान की है, जरुरत है उस शक्ति को पहचानने व सही राह दिखाकर उसे तराशने की। अर्पण कल्याण समिति द्वारा संचालित मूक-बधिर बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल व छात्रावास का संचालन एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के लिए भविष्य में कुछ भी जरुरत पड़े तो वे सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रायपुर नगर निगम के सभापति एवं पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि पिछले 7 माह में इन बच्चों में जो बदलाव देखने को मिला है वह अभूतपूर्व है। इस स्कूल में शिक्षक बच्चों को शिक्षा ही नहीं अपितु संस्कार भी प्रदान कर रहे हैं। जब ये बच्चे जुलाई माह में इस स्कूल में पढ़ाई करने आए थे तो उनके रहन-सहन, खान-पान का तौर-तरीका कुछ और ही था और आज ये बच्चे पूरी तरह से संस्कारवान हो गए है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकगण बधाई के पात्र हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में अर्पण कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां पढ़ाई करने वाले बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें पाठ्य सामग्रियों के अलावा स्कूल यूनिफार्म, जूते-मोजे भी निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को निःशुल्क हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की गई है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अरुण सिंघानिया ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वह सराहनीय है। संस्था का यह नेक कार्य अनुकरणीय है। इन बच्चों के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो यह मेरा सौभाग्य होगा। भविष्य में किसी भी तरह की जरुरत पड़ने पर मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। डब्ल्यूएचओ द्वारा तीन मार्च को मनाए जाने वाले विश्व श्रवण दिवस के बारे में जानकारी ऑडियोलॉजिस्ट डा. राकेश पांडेय, डा. देव मिश्रा और स्पीचथैरेपिस्ट डा. रुचिरा पांडेय ने दी। इस अवसर पर प्रसिद्ध ईएनटी विशेषज्ञ डा. सतीश राठी ने कहा कि कान से संबंधित समस्याओं को हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। समय रहते उपचार होने पर समस्याओं से बचा जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि समय रहते विशेषज्ञों के पास पहुंचे तो हर बीमारी का उपचार संभव है। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर के अध्यक्ष भरत डागा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां कैश काउंटर नहीं है। श्री डागा ने कहा कि रोटरी क्लब का उद्देश्य समाज के जरुरतमंद लोगों तक उनकी मूलभूत सुविधा मुहैया कराना है और यह कार्य निरंतर जारी है। कार्यक्रम का संचालन सीमा छाबड़ा ने किया।

इस अवसर पर रायपुर क्लब ऑफ रोटरी के सुभाष साहू, सोम अग्रवाल, नवीन आहुजा, गिरीश वोरा, दमयंती, कृष्ण प्रिया डागा समेत अनेक रोटेरियन और हितवाद के जीएम अनिल पवार, कामधेनु विश्व विद्यालय के प्रोफेसर डॉ राकेश मिश्रा, अर्पण कल्याण समिति के उपाध्यक्ष धनंजय त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष विरेन्द्र शर्मा, संचालक मृत्युंजय शुक्ला, स्कूल के प्राचार्य कमलेश शुक्ला आदि उपस्थित थे।

भाजपा में भोजन की राजनीति

भाजपा के अंदरखाने में भोजन की राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। खबर है कि पिछले दिनों तय कार्यक्रम के अनुसार भाजपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी को दुर्ग में पार्टी के एक जमीनी कार्यकर्ता के घर पर

भोजन करने जाना था। सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन एनवक्त पर राष्ट्रीय पदाधिकारी दुर्ग की एक कद्दावर राजनेता के निवास पर भोजन करने चले गए। कहते हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी के कद्दावर राजनेता के निवास पर भोजन पर जाने से एक सांसद ने कार्यक्रम में ही अपना भड़ास निकाला और छोटे नेताओं की उपेक्षा और बड़े नेताओं को तवज्जो देने को राज्य में पार्टी की हार का बड़ा कारण बता दिया। बताते हैं डेमेज कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी बाद में जमीनी कार्यकर्ता के घर चाय पीने गए। कहा जा रहा है कि दुर्ग की ताकतवर राजनेता ने राष्ट्रीय पदाधिकारी को अपने निवास पर भोजन पर आमंत्रित करने के लिए प्रदेश संगठन के एक पदाधिकारी से एप्रोच भी लगाया। राष्ट्रीय पदाधिकारी को भोजन पर आमंत्रित कर दुर्ग के ताकतवर राजनेता की ताकत में कितना इजाफा हुआ, ये तो वे ही जान सकती हैं, पर भोजन पॉलिटिक्स से दुर्ग की राजनीति में उबाल आ गया है।

सिंहदेव का होली मिलन कार्यक्रम

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सात मार्च को अंबिकापुर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

कही-सुनी

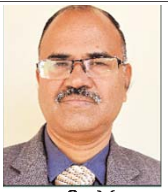

रवि भोई

वैसे तो सरगुजा के राजमहल में होली मिलन कार्यक्रम

की परंपरा सालों पुरानी है, पर कहते हैं मंत्री बनने के बाद टीएस सिंहदेव ने आयोजन बंद कर दिया था। 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव लड़ने और न लड़ने को लेकर टीएस सिंहदेव के कई बयान आ चुके हैं। मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस भी उनकी जुबान पर आ ही जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। सरगुजा के लोग भी उन्हें 2018 के पहले भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। भूपेश बघेल बाजी मार ले गए। अब होली मिलन के बहाने क्या संदेश देना चाहते हैं, उस पर सबकी नजर है।

कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं में बहस ?

विधानसभा के एक कक्ष में कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों नेता अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सुप्रीम है। कहते हैं एक मंत्री जी का दुख दोनों नेताओं के बीच बहस का कारण बन गया। मंत्री जी को एक नेताजी का काफी करीबी माना जाता है। नेताजी मंत्री जी को हमेशा आगे बढाने में लगे रहते हैं। मंत्री पद भी नेताजी की मेहरबानी से मिली है। मंत्री जी की पीड़ा से नेताजी में सहानुभूति जाग गई और उन्होंने मंत्री जी का पक्ष ले लिया। इससे दूसरे नेताजी नाराज हो गए और दोनों के बीच तीखी तकरार हो गई।

कुलबुलाते भाजपा के आदिवासी नेता

कहते हैं भाजपा के आदिवासी नेता आरक्षण के मुद्दे

पर पार्टी फोरम में अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन संगठन ने उनका मुंह बंद कर दिया है। ऐसे में वे अपने व्हाट्सप ग्रुप में भड़ास निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा सांप के फन की तरह हो गया है। भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य में 76 फीसदी आरक्षण का विधेयक पारित कर दिया है। राजभवन में विधेयक अटका है। चर्चा है कि इस मसले पर भाजपा चुप्पी साधे हुए है और अपने आदिवासी विधायकों को भी मौन रहने की नसीहत दे रखी है।

बजट पर निगाहें

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट सोमवार को विधानसभा में पेश करेंगे। चुनावी साल के बजट पर सबकी निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि बजट सवा लाख करोड़ के आसपास का होगा। संभावना है कि आखिरी बजट चुनावी होने के साथ-साथ लुभावनी भी होगा और भूपेश बघेल का बजट किसान और गांव को प्राथमिकता देने वाला होगा। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का दांव चला है। इस बजट में उसके लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा। संविदा, अस्थायी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी सरकार की तरफ देख रहे हैं। इसके आलावा शराब को लेकर सरकार की नीति का भी सभी को इंतजार है।

छत्तीसगढ़ में पुलिस सुस्त, अपराधी चुस्त

राजधानी रायपुर में जिस तरह चाकूबाजी और

हत्या की घटनाएं बढ़ गईं हैं , उससे लगता है पुलिस सुस्त पड़ गई है और अपराधी चुस्त हो गए है। अपराधियों के हौसले राजधानी में ही नहीं, बिलासपुर, भिलाई और दूसरे शहरों -कस्बों में भी बुलंद हो गए हैं। राजधानी के पाश कालोनी में कैंची मारकर दिनदहाड़े एक युवक की हत्या बताता है कि राज्य में पुलिस का इकबाल बचा नहीं है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आबादी बढ़ी है, पर पुलिस फ़ोर्स भी बढ़ा है। थाने और चौकियां भी बढ़ी हैं। सुविधाएं भी बढ़ीं हैं, फिर भी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं ? इस पर पुलिस के आला अफसरों को चिंतन-मनन करना होगा और नए सिरे से प्लानिंग करनी होगी।

बिना नैक ग्रेड के रविशंकर यूनिवर्सिटी

छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर बिना नैक ग्रेड के ही चल रहा है। कहते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल (नैक) से पांच साल पहले रविशंकर यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला था , वही चल रहा है। कहा जा रहा है नैक ग्रेड के लिए विश्वविद्यालय को जनवरी तक का एक्सटेंशन मिला था , वह अवधि भी खत्म हो गई है। चर्चा है कि कुलपति प्रो. के एल वर्मा के कार्यकाल में नैक से मूल्यांकन कराया ही नहीं गया। खबर है कि डॉ. वर्मा के कार्यकाल में न तो टीचिंग स्टाफ की भर्ती हुई और न ही दूसरे स्टाफ की। डॉ. वर्मा का कार्यकाल एक अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। प्रोफ़ेसर सच्चिदानंद शुक्ला को रविशंकर यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। अब देखते हैं नए कुलपति क्या करते हैं ?

भाजपा प्रधानमंत्री आवास पर झूठ की राजनीति कर रही -कांग्रेस

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास पर भाजपा झूठ बोलकर भ्रम फैला रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता राज्य में प्रधानमंत्री आवास को लेकर अलग-अलग आंकड़े बताकर फर्जीगिरी की राजनीति कर रही है। राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के काम प्रगति पर है। मुद्दाविहीन भाजपा आम जनता से गलत फार्म भरवा कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। प्रदेश में कुल शहरी और ग्रामीण मिलाकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1,304,000 (तेरह लाख चार हजार) आवास स्वीकृत हुये है। प्रदेश में 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी हुई जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण

हो चुके है, शेष में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2 लाख 69 हजार मकान स्वीकृत हुये। प्रधानमंत्री आवास के शहरी क्षेत्र का ही यदि तुलनात्मक अध्ययन करे तो रमन सिंह सरकार ने 4 साल में शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान बनाये थे तथा भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाये है। रमन सरकार ने चार साल में मात्र 272 करोड़ रू. का राज्यांश दिया था इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने 4 साल में 2100 करोड़ शहरी आवास में राज्यांश दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा न देने पड़े इसलिये प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति में हमेशा कोताही बरतती है। गरीबों के आशियाने के सपने को चकनाचूर करने वाले गरीबों के हितैषी बनने का पाखंड कर रहे हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ में राज्य शासन पर झूठा आरोप लगाकर प्रधानमंत्री आवास पर भ्रम फैलाती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की।

मोर आवास मोर अधिकार रोक रहे हैं भूपेश सरकार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के आवास छीना। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि क्या किसी योजना में सिर्फ प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है इसीलिए प्रदेश की आम गरीब जनता को उस योजना का लाभ आप नहीं देंगे। स्तरहीन बयानों के लिए पहचान बना चुकी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार गरीबों के सबसे बड़े सपने को पूरा नहीं होने दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक आवासहीन को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की जिसका लक्ष्य था कि 2022 तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं का मकान हो। कोरोना काल के कारण इसे बढ़ाकर 2024 किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 सर्वे सूची के अनुसार मकान बनने थे फिर 2016 में आवास प्लस के नाम से केंद्र सरकार ने एक योजना

भाजपा की सरकार ने बनाएं मकान

वर्ष	छत्तीसगढ़ को मिला लक्ष्य	आवास पूर्ण
2016-17	2,32,903	2,30,000
2017-18	2,06,000	2,01,000
2018-19	3,48,960	3,25,765
	7.87 लाख	7.56 लाख

लाई। जिसमें 2011 की सर्वे सूची में छूटे नाम तथा किन्हीं कारणों से 2011 के रद्द आवेदन को मिलाकर फिर सर्वे सूची बनाई गई जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल 16 लाख हितग्राही पाए गए। योजना प्रारंभ होने के प्रथम वर्षों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस दौरान हमने लगभग 7.50 लाख मकान बनाएं।

उन्होंने कहा कि 2018 के पहले देश में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ अव्वल स्थान में था। लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गए । साथ ही पूर्व में जो मकान बन रहे थे उनकी किश्त भी इस भूपेश सरकार ने देनी बंद कर दी। पिछले 4 वर्ष में भूपेश सरकार में यह सारे कार्य बंद पड़े हैं और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की आस में अपनी झोपड़िया तोड़ दी वे भी अब किराए के मकान में रहने को बाध्य है और दोहरी मार झेल रहे है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है इसलिए पूरा पैसा प्रधानमंत्री जी भेजें। आजादी के बाद सालों साल देश में अनेक योजनाओं सड़कों और इमारतों के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब के नाम से ही पैसे की बंदरबांट कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी जरा स्पष्ट करें कि उपरोक्त योजनाओं में देश का और छत्तीसगढ़ प्रदेश का पैसा था या गांधी परिवार के घरों से पैसे आते थे। गरीब के सपने को तोड़ने के लिए ऐसा स्तरहीन बयान प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक लक्ष्य निर्धारित योजना है जिसके तहत समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में केंद्र के मंत्री व सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा लगातार प्रदेश सरकार से पत्र व्यवहार कर कार्य में प्रगति लाने का अनुरोध किया जाता रहा। केंद्र सरकार ने 17 जून 2021 और 6 जुलाई 2021 को सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना में गति लाने के लिए पत्र व्यवहार किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ में आप का चुनावी शंखनाद, केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे जनसभा

रायपुर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय

संयोजक व दिल्ली के केबिनेट मंत्री गोपाल राय शनिवार को रायपुर पहुंचे. कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता की. गोपाल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने 15 साल भाजपा को मौका दिया. 4 साल हो गए कांग्रेस को सरकार चलाते हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिस अरमानों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था, आज वह अधूरा है. आदिवासी अलग परेशान हैं, किसान अलग परेशान हैं, नौजवान अलग परेशान हैं, महिलाएं अलग परेशान है, स्कूल और अस्पतालों की स्थिति काफी जर्जर है. ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं. आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में एक मजबूती के साथ विकल्प दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत रविवार से करने जा रही है. जोरा के मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यकर्ताओं से संवाद करने आ रहे हैं।

सभी जिलों में मुख्यमंत्री के बजट भाषण का प्रसारण करेगी कांग्रेस

रायपुर। 6 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मुख्यमंत्री के बजट भाषण को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में एलईडी के माध्यम से लाईव प्रसारण कर कार्यकर्ताओं सहित आमजनता को दिखाये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सभी प्रदेश पदाधिकारियो, सांसद, पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, पदाधिकारियो, मोर्चा, संगठन, प्रकोष्ठ विभाग के जिला, ब्लाक पदाधिकारियों, सोशल मीडिया के प्रशिक्षिति सदस्यों, नगरीय निकाय, त्रि स्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, सहकारिता क्षेत्र के पदाधिकारियों, वरिष्ठ कांग्रेसजन कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे 6 मार्च 2023 को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट भाषण को बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाईव प्रसारण कर हर्षोल्लास के साथ बजट का स्वागत करते हुये खुशियां मनायें।

सूर्यकांत की मां-भाई को जमानत नहीं

रायपुर। स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत ने मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन में कथित लेवी के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी की मां और भाई को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. वहीं, आईएएस समीर विश्नोई की पुलिस रिमांड की मांग पर 6 मार्च के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन में कथित लेवी के मामले में शनिवार को स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में सुनवाई हुई. आज सूर्यकांत तिवारी की मां कैलाश तिवारी और भाई रजनीकांत तिवारी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी. इसे स्पेशल जज ने खारिज कर दिया. ईडी ने दूसरे चालान में दोनों को आरोपी बनाया था. इसके अलावा ईडी की ओर से आईएएस विश्नोई से पूछताछ और जांच के संबंध में रिमांड की मांग की गई थी. इस आज फर्स्ट हाफ में बहस हुई. शाम को स्पेशल जज ने फैसला 6 मार्च के लिए सुरक्षित रखने की जानकारी दी. मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद आईएएस विश्नोई, सूर्यकांत, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया आदि की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने सबकी न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. इधर, जेल में बंद आरोपी राजेश चौधरी की ओर से जमानत के लिए आवेदन किया गया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज में पॉलिसी पैरालिसिस- अमित चिमनानी

रायपुर। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय 10 प्रतिशत से बढ़ने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि 10 प्रतिशत आय बढ़ने पर इतराने वाली कांग्रेस सरकार से हमारा प्रश्न है कि जब 2003 में छत्तीसगढ़ की गिनती बीमारू राज्य में होती थी प्रदेश का बजट केवल 6 हजार से 9 हजार करोड़ रुपए था सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे राज्य की खुद की कोई आय नहीं थी केंद्र से भी कोई खास मदद नहीं मिलती थी ऐसे चुनौती के समय में भी भाजपा की सरकार में 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय लगभग 18 प्रतिशत तक बढ़ती रही। अमित चिमनानी ने कहा 2003 में प्रति व्यक्ति आय 12 हजार रु थी जबकि भाजपा के शासन जाते-जाते वह 92 हजार रुपए हो चुकी थी आज तो प्रदेश का बजट एक लाख करोड से ज्यादा हो गया है राज्य की खुद की आय लगभग 50 हजार करोड है केंद्र से भी ?50 हजार करोड़ मिलते हैं ऐसे में प्रति व्यक्ति आय महज 10 प्रतिशत बढ़ना कांग्रेस के कुशासन का परिणाम है गलत नीतियों का परिणाम है छत्तीसगढ़ पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा है जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ बना अपराधगढ़ और रायपुर बन गया चाकूपुर - केदार गुप्ता

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया है और अपराधी गिरोह बना कर अपराध कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में अपराधियों ने प्रदेश भर में आतंक मचा रखा है। प्रदेश की जनता सट्टेबाजी से पहले ही परेशान थी, युवा नशे के आदी हो रहे हैं, अब नौनिहाल सूदखोरों के चंगुल में फंस कर जान गवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है और राजधानी रायपुर चाकूपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से रायपुर में 2000 रुपए के लिए कैंची मारकर किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी घर का चिराग बुझा दिया जाता है। अपराधी यह सब पुलिस की नाक के नीचे संगठित गिरोह बनाकर कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल करते हुए कहा कि रायपुर में दो-दो आईजी काम कर रहे हैं, इसके बाद भी राजधानी रायपुर में अपराध करने में अपराधी जरा भी नहीं घबरा रहे हैं। अपनी सरकार को चूड़ियां भेजने की बजाय कांग्रेस नेता भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करने वाली ईडी को चूड़ी भेजकर उसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को अगर चूड़ी भेजने का इतना ही शौक है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाने वाले पुलिस अधिकारियों को भेजें। प्रदेश सरकार के मुखिया को चूड़ी भेंट करें।

विधानसभा घेराव को लेकर भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक संपन्न

दुर्ग। आगामी 15 मार्च को रायपुर में होने वाले विधानसभा भवन घेराव को लेकर भाजपा की संभागीय बैठक दुर्ग जिला कार्यालय में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में दुर्ग, भिलाई राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, मानपुर मोहला जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के पश्चात दुर्ग जिले के निषाद समाज के जिलाध्यक्ष घनश्याम निषाद के नेतृत्व में निषाद समाज के 50 लोगों को छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने भाजपा का गमछा पहना कर पार्टी प्रवेश कराया। बैठक में रायपुर में होने वाले विधानसभा घेराव एवं बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा करते हुए दायित्वों का निर्धारण किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि प्रदेश भाजपा का कार्यक्रम मोर आवास, मोर अधिकार अभियान आवासहीन गरीब जनता के हितों को लेकर है और भारतीय जनता पार्टी संकल्प बद्ध है कि गरीबों को उनका आवास दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 मार्च को समस्त हितग्राहियों को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इससे पहले भाजपा हितग्राहियों के साथ बैठक करके सरकार को आवेदन दे चुकी है, विधायकों को जगाने के लिए भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों का घेराव किया है। परंतु यह सरकार आवासहीन गरीबों की ओर आंख मूंदकर बैठी है। विधानसभा घेराव कर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे प्रदेश में तत्काल लागू करें और गरीबों का हक दें। बैठक को संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी ने भी संबोधित किया। आभार प्रदर्शन दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने एवं संचालन दुर्ग जिला महामंत्री सुरेंद्र कौशिक ने किया।

कांग्रेस मोदी की योजनाओं को रोकने का काम कर रही है-अरुण

भाजपा किसान मोर्चा का दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग प्रारम्भ

रायपुर। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग रायखेड़ा में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा भाजपा के मोर्चों मे मोर्चा है। भारतीय जनता पार्टी विचार के लिये काम करती है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार के लिए काम करती है। हमारा विचार समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की भलाई के लिये काम करने वाला विचार है। अंत्योदय के हित में काम करने वाला विचार है। साहूकारों के चंगुल से

किसानों को मुक्त करने के लिये अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई और किसानों को ब्याज के बोझ से मुक्ति दिलाई। उन्होंने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया और किसानों का जीवन सुगम किया। वहीं जब से केंद्र में मोदीजी की सरकार बनी है तबसे गरीब और छोटे किसानों के कल्याण की अनेक योजनाएं काम कर रही हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत देश के 11 करोड़ किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपया मिल रहा है। यूरिया और डीएपी के दाम कम रखने के लिये मोदी सरकार 50त्न अनुदान दे रही है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य मे जबरदस्त बढोतरी की है। जहां कांग्रेस सरकार इसके लिए 25000 करोड़ खर्च करती थी वहीं मोदी सरकार इससे 5 गुना अधिक 125000 करोड़ का खर्च करती है। किसानों के कच्चे आवास की चिंता करते हुए मोदीजी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है और उनके मकानो को पक्का करने का काम कर रहे हैं। मोटे अनाज उगाने वाले किसानों को लाभ देने के लिये भी मोदी सरकार ने बड़ी राशि आबंटित की है। किसानों की फसल को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू है जिसमें फसल के 30त्न नुकसान होने पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है। ड्रिप सिंचाई और पशुपालन व मत्स्य पालन जैसी कई योजनाएं लागू हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश बघेल की सरकार को आड़े हांथों लेते हुए कहा कि ये गरीब विरोधी सरकार है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोदीजी की योजनाओं मे अड़ंगे लगाकर उन्हे रोकने का काम कर रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.